https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

# कमल संदेश

भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन संपन्न

वर्ष-13, अंक-10 16-31 मई, 2018 (पाक्षिक) ₹20

## अब हर गांव हुआ रौशन

भारतीय संस्कृति में अर्थ | बदलती दुनिया में उभरता भारत | कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर विशेष

# भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के भोपाल (मध्य प्रदेश) प्रवास की छवियां

भोपाल (मध्य प्रदेश) में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते मध्य प्रदेश भाजपा नेतागण

भोपाल में आयोजित विशाल बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

भोपाल की बैठक में आए उत्साहित कार्यकताओं के दृश्य

# कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

**संपादक**
प्रभात झा

**कार्यकारी संपादक**
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

**सहायक संपादक**
संजीव कुमार सिन्हा

**संपादक मंडल सदस्य**
सत्यपाल
राम नयन सिंह

**कला संपादक**
विकास सैनी
मुकेश कुमार

**संपर्क**
फोन: +91(11) 23381428

**फैक्स**
फैक्स: +91(11) 23387887

**ई-मेल**
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

**वेबसाइट:** www.kamalsandesh.org


# विषय-सूची

## 06 हर गांव में पहुंची बिजली

आजादी के सत्तर साल के लंबे इंतज़ार के बाद 28 अप्रैल को अंततः हर गांव में बिजली पहुंची। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के सघन प्रयासों के चलते अभी तक अंधेरे में डूबे 18 हजार से अधिक गांवों में अब बिजली पहुंच गयी है। दरअसल, मणिपुर का लीसांग देश का आखिरी गांव था, जहां बिजली...


## वैचारिकी

भारतीय संस्कृति में अर्थ 15

## श्रद्धांजलि

के. जना कृष्णमूर्ति / बी. एन. विजय कुमार 16

## लेख

कश्मीर की वेदी पर वह आत्मबलिदान 26

बदलती दुनिया में उभरता भारत 32

## अन्य

श्रमिकों को 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से जोड़ने की आवश्यकता : नितिन गडकरी 17

हम विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं: नरेन्द्र मोदी 18

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार से विकास नहीं हो पाया: अमित शाह 22

प्रधानमंत्री की अनौपचारिक चीन यात्रा 28

मन की बात 30

मार्च 2019 तक 70-80 प्रतिशत स्वच्छ होंगी गंगा 31

## स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 08


## 09 राज्य में भाजपा को हराने का कांग्रेस में दम नहीं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 मई को भोपाल (मध्य प्रदेश) के भेल दशहरा ग्राउंड में आयोजित प्रदेश स्तरीय विस्तारित...

## 11 राकेश सिंह बने म.प्र. भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 अप्रैल को श्री राकेश सिंह,...

## 12 अप्रैल 2018 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक

अप्रैल, 2018 में सकल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 1,03,458...

## 24 मंत्रिमंडल ने 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' को जारी रखने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति...


प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

## twitter

### @narendramodi

कर्नाटक चुनाव-2018 भाजपा के विकास एवं एकता के एजेंडे और कांग्रेस के विकास विरोधी एवं विभाजनकारी राजनीति के बीच हैं।

### @AmitShah

कांग्रेस अब पूरी तरह समझ चुकी है। वे जानते हैं कि कर्नाटक में उनका भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का शासनकाल खत्म हो रहा है। यही कारण है कि वे सफल होने के लिए अनैतिक और अलोकतांत्रिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, उनके प्रयासों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और लोकशक्ति की जीत होगी।

### @myogiadityanath

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, राज्य सरकार महिलाओं की आत्मनिर्भरता और कल्याण के लिए हरसम्भव कदम उठाने के लिए तत्पर है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समाज को भी आगे आकर अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। समाज व राष्ट्र के साथ हो रहे अपराध पर मौन रहना भी अपराध है।

## facebook

कृषि प्रधान प्रदेश राजस्थान में राजस्व से संबंधित समस्याएं किसानों, काश्तकारों, ग्रामीणों आदि के लिए ज़ी का जंजाल बनी हुई थीं। राजस्व से जुड़े सामान्य मुकदमों को निपटने में जहां औसतन चार से पांच साल का समय लग जाता था, वहीं कई मुकदमें सुलझने में लोगों को जिंदगी भर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसी समस्याओं से जनता को निजात दिलाने और त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए हमने न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की खास बात यह है कि 17 से ज्यादा विभागों के अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर मौके पर ही मुकदमों का समाधान करते हैं।

— वसुंधरा राजे

कांग्रेस गंभीर नेतृत्व नहीं दे पाई है। जिस ढंग की राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें परिपक्वता का अभाव दिखता है। कोई कह भी नहीं रहा और वे खुद बोल रहे हैं कि "मैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं।" उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि लोग कहते हैं कि वे शेखचिल्ली और मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं। सिद्धारमैया ने अंग्रेजों की "फूट डालो राज़ करो" की नीति अपनाई और समाज को बांटने का काम किया। उन्होंने कभी सकारात्मक राजनीति की ही नहीं है। चुनाव जीतने के लिए समाज को बांट रहे हैं। हिन्दू समाज को बांटने का षड्यंत्र किया।

— शिवराज सिंह चौहान

सभार : सोशल मीडिया

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
'गंगा दशहरा'
की हार्दिक शुभकामनाएं!

# विकास का नया उजाला

लीसांग में बिजली का बल्ब जलने के साथ ही देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। मणिपुर में बसा यह 38 परिवारों और 200 से भी अधिक लोगों के इस गांव के लिये अब नई संभावनाओं के द्वार खुल चुके हैं। बिजली पहुंचने के साथ ही इस गांव के लोग नये आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही एक विशेष प्रकार की राहत और संतोष का भाव उनके चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। गांव में उत्सव और उत्साह का माहौल है। गांव के इस वातावरण को वहां के सचिव लालबोई के शब्दों में एक समाचार पत्र ने इस तरह से वर्णन किया, ''उस रात रोमांच के कारण हममें से कोई नहीं सोया, यहां तक कि बच्चे भी नहीं। बच्चे पूरे समय मैदानों में दौड़ते रहे। हम सरकार के बहुत आभारी हैं। हमारी खुशी को कोई भी शब्द व्यक्त नहीं कर सकते।'' लोग अपने गांव को मिले नये रूतबे का जश्न मना रहे हैं तथा अपनी विकास की गाथा लिखने के लिये तत्पर हैं। सबको पता है कि इस एक कदम से उनके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।

नये भविष्य के स्वागत में इस प्रकार के रोमांच का अनुभव करने वाला लीसांग अकेला नहीं है। बचे हुए 18,452 गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पायी थी, इस रोमांच और उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। इन गांवों को बिजली मिलने की तब तक कोई उम्मीद भी नहीं थी, जब तक प्रधानमंत्री ने इनके लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की। लालकिले के प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 1000 दिन के अंदर इन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी। दूर–दराज इलाकों में स्थित ये गांव जो जंगलों–पहाड़ों में बसे थे, देश की विकास यात्रा में काफी पीछे छूट गये थे। अपने दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में काफी नीचे थे। इन गांवों में रहने वाले निराशा एवं अंधकार में जीवन बसर करने को मजबूर थे। बिजली न होने के कारण विकास के अनेक अवसरों से वे वंचित हो गये थे। अनेकों अवसरों के द्वार इन ग्रामीणों के लिये बंद हो गए थे। बिजली आ जाने से अब वे द्वार खुल चुके हैं। सामान्य रफ्तार से इन गांवों के जीवन में उजाला लाने में वर्षों लग जाते, परन्तु वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प ही था की लक्ष्य को समय से पहले मात्र 987 दिनों में पूर्ण कर लिया गया।

> सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद, सरकार का ध्यान अब घर–घर में जहां अब तक अंधेरा है, वहां बिजली पहुंचाने पर है। इससे भारत की विकास यात्रा अत्यधिक तीव्र होगी तथा करोड़ों लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आयेगा। आज बिना बिजली के विकास का स्वप्न अधूरा है।

प्रधानमंत्री का लक्ष्य इन उपेक्षित गांवों को देश की विकास यात्र में शामिल कर 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को साकार करने का था। इस मंत्र की अवधारणा न केवल सबको साथ लेकर चलने में निहित है, बल्कि गरीब, वंचित एवं शोषित वर्गों के लिये विशेष कार्य–योजना क्रियान्वित करने की भी है। देश के सर्वांगीण विकास के लिये भाजपा एकात्मता की राह पर चलने पर विश्वास करती है और मानती है कि जब तक समाज का कोई एक भाग भी पिछड़ा है, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाकर समाज के इस वंचित हिस्से को विकास के मार्ग पर चलने के लिया ऊर्जा मिली है और अब वे नये जोश एवं उमंग से पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं।

जहां एक ओर पूरा देश इस अनुपम उपलब्धि को सराह रहा है और उत्सव मना रहा है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का एक वर्ग हास्यास्पद तरीके से इसे नकारने की कोशिश में है। इससे कांग्रेस की ही देश भर में फजीहत हो रही है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि इस प्रकार की उपलब्धियां पूरे देश के लिये गौरव का विषय है न कि किसी एक राजनीतिक दल का। आने वाले दिनों में इस प्रकार के अवसर का स्वागत करने के लिये कांग्रेस को मानसिक रूप से तैयारी कर लेनी चाहिये, क्योंकि उपलब्धियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ने ही वाली है। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद, सरकार का ध्यान अब घर–घर में जहां अब तक अंधेरा है, वहां बिजली पहुंचाने पर है। इससे भारत की विकास यात्रा अत्यधिक तीव्र होगी तथा करोड़ों लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आयेगा। आज बिना बिजली के विकास का स्वप्न अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दूरगामी निर्णय के लिये बधाई के पात्र हैं, जो हर गांव एवं हर घर बिजली पहुंचाकर करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भरने का कार्य कर रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

# हर गांव में पहुंची बिजली

## समय सीमा से पहले पूरा हुआ लक्ष्य

आजादी के सत्तर साल के लंबे इंतज़ार के बाद 28 अप्रैल को अंततः हर गांव में बिजली पहुंची। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के सघन प्रयासों के चलते अभी तक अंधेरे में डूबे 18 हजार से अधिक गांवों में अब बिजली पहुंच गयी है। दरअसल, मणिपुर का लीसांग देश का आखिरी गांव था, जहां बिजली पहुंचाई गयी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से एक हजार दिन के भीतर इन गांवों में बिजली पहुंचाने की घोषणा की थी और यह लक्ष्य समय सीमा पूरी होने से 12 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। इन गांवों में बिजली पहुंचने के बाद देश के सभी गांव अब विद्युतीकृत हो गए हैं। अब मार्च, 2019 तक हर घर को बिजली देने का काम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उल्लेखनीय है कि 10 प्रतिशत विद्युतीकृत परिवारों वाले गांव को विद्युतीकृत गांव कहा जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को ट्वीट कर कहा- 'भारत की विकास यात्रा में 28 अप्रैल 2018 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। कल हमने एक वादा पूरा किया, जिससे कई भारतीयों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के हर गांव में बिजली पहुंच गई है।'

**'भारत की विकास यात्रा में 28 अप्रैल 2018 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। कल हमने एक वादा पूरा किया, जिससे कई भारतीयों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के हर गांव में बिजली पहुंच गई है।'**

श्री मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, 'मणिपुर के लीसांग जैसे पूरे भारत के हजारों अन्य गांवों को सशक्त बनाया गया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं उन लोगों के प्रयासों को सलाम करता हूं, जिन्होंने अथक रूप से जमीन पर काम किया है। अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य सभी लोगों की टीम ने एक शक्तिशाली भारत के सपने को वास्तविकता बनाने के लिए काम किया।'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, 'आज पूरा देश हर गांव में बिजली का जश्न मना रहा है, जबकि कांग्रेस एक परिवार के हाथ से सत्ता के जाने का शोक कर रही है।' देश के हरेक गांव तक बिजली पहुंचने पर केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बधाई दी और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया।

दरअसल, बिजली मंत्रालय ने यह काम एक मई 2018 तक पूरा करने की योजना बनायी थी, लेकिन इसे 28 अप्रैल को ही पूरा कर लिया गया। जिन गांवों में सबसे बाद में बिजली पहुंची है वे घने जंगल या दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हैं।

जिन गांवों में बिजली पहुंचायी गयी है उसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों के गांव हैं। साथ ही सात हजार से अधिक गांव नक्सल और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इसलिए यहां बिजली पहुंचाना बहुत मुश्किल था। हर गांव में बिजली पहुंचाने के बाद सरकार का अगला लक्ष्य 'सौभाग्य' योजना के जरिए हर घर तक बिजली पहुंचाने का है। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। ■

# विश्व बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा- 85 प्रतिशत आबादी तक पहुंची बिजली

**विश्व** बैंक ने विद्युतीकरण में भारत के काम को अत्यंत बेहतर माना है। देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी तक बिजली पहुंच चुकी है। 2010 और 2016 के बीच भारत में हर साल तीन करोड़ लोगों को बिजली मुहैया कराई गई। यह अन्य किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा है।

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट से उसकी पुष्टि होती है। विश्व बैंक की प्रमुख ऊर्जा अर्थशास्त्री विविएन फोस्टर ने कहा कि 1.25 अरब की आबादी वाले देश में शेष 15 प्रतिशत को बिजली मुहैया कराने की चुनौती बनी हुई है। भारत 3030 तक बिजली पहुंचाने का वैश्विक लक्ष्य साध लेगा। उन्होंने कहा कि आंकड़ा भारत सरकार के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा है। इससे आपको हैरत हो सकती है।

गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की सौभाग्य योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक की तरफ मोदी सरकार की सराहना की जा चुकी है।

दरअसल, सरकार वर्तमान में 80 प्रतिशत आबादी तक बिजली पहुंचने की जानकारी दे रही है। विश्व बैंक की कार्य प्रणाली घरों के सर्वे पर आधारित है। इसमें उन्हें भी शामिल किया जाता है जो ऑफ ग्रिड हैं, जबकि सरकार का आंकड़ा अधिकृत रूप से लिए गए संपर्क पर आधारित है। फोस्टर ने कहा कि कुल मिलाकर भारत किसी अन्य देश की तुलना में कहीं ज्यादा विद्युतीकरण कर रहा है।

# 'सौभाग्य' यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

**प्रधानमंत्री** सहज बिजली हर घर योजना यानी 'सौभाग्य' के तहत अब तक करीब 52 लाख घरों तक बिजली पहुंचायी जा चुकी है और इस योजना के तहत मार्च 2019 तक 3.63 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना पर 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने 2018-19 के बजट में 2750 करोड़ रुपए 'सौभाग्य' के लिए दिए हैं। यह करोड़ों परिवारों के घर में नयी रोशनी लाने के लिए है, जिनके घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी अंधेरा है।

'सौभाग्य' योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितंबर को किया था। इसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चत करते हुए सभी घरों में बिजली पहुंचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सौभाग्य योजना के तहत हर ग्रामीण व शहरी व्यक्ति जो 2011 की सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को फ्री बिजली कनेक्शन देना है। जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं उनको 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाना है। यह राशि एक मुश्त ना लेते हुए 50 रुपए प्रति माह बिजली बिल के साथ वसूली जाएगी। साथ ही निःशुल्क 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा, एक डीसी बैटरी कनेक्शन धारक को देने का प्रावधान है। इसके साथ ही पांच वर्षों तक मरम्मत और देखभाल भी की जाएगी। दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में बिना बिजली वाले घरों में बैटरी बैंक सहित 200 से 300 डब्ल्यूपी वाले सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाएंगे।

## योजना के अपेक्षित परिणाम

1. रोशनी के लिए केरोसिन का प्रयोग न करने से पर्यावरण में सुधार
2. शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति
3. उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं
4. रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल द्वारा बेहतर संपर्कता
5. आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में वृद्धि
6. विशेष रूप से महिलाओं सहित सभी के जीवन स्तर में सुधार

योजना के अंतर्गत लाभकर्ताओं की पहचान, बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, आवेदक का चित्र और पहचान का प्रमाण हाथो-हाथ पंजीकृत किया जा रहा है। दरअसल, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) देश भर में योजना के संचालन के लिए नोडल संस्था है।

## समावेशी ऊर्जा

भारत के सभी गांवों तक बिजली की पहुंच हो जाना निश्चय ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। देश के विकास के सफर में यह मुकाम हासिल हुआ अट्ठाईस अप्रैल की शाम को, जब मणिपुर के सेनापति जिले में आने वाला लाइसंग गांव नेशनल पॉवर ग्रिड से जुड़ने वाला आखिरी गांव बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जहां इसे भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन कहा, वहीं गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम करने वाली नोडल एजेंसी आरईसी यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने एलान किया कि देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक हजार दिनों के भीतर संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण का वादा किया था। तब कोई 18,450 गांव ही रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। उन तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 75,893 करोड़ रुपए आबंटित किए। बाद में पता चला कि कोई बारह सौ गांव और भी हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। इस तरह इस योजना ने अपनी मंजिल पा ली है, और इसमें वैसी देरी या ढीलमढाल भी नहीं हुई जो कि अमूमन सारी सरकारी योजनाओं में दिखती है।

शायद प्रधानमंत्री की दिलचस्पी के कारण संबंधित महकमों ने इस योजना को लेकर एक मिशन की तरह काम किया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पहले हुए कामों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जब देश आजाद हुआ तब विद्युतीकरण के दायरे में केवल पंद्रह हजार गांव थे। वर्ष 1991 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या 4 लाख 81 हजार से ज्यादा हो गई। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2015 तक देश के 97 फीसद गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। यानी जब प्रधानमंत्री ने बिजली से वंचित गांवों तक एक हजार दिनों के भीतर बिजली पहुंचा देने का वायदा किया, तब सिर्फ तीन फीसद गांव ही रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। अगर राज्यों के हिसाब से देखें, तो बहुत-से राज्यों ने पहले ही संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य पा लिया था। लेकिन विद्युतीकरण का यह बचा-खुचा दौर काफी चुनौतियों भरा था, क्योंकि विद्युतीकृत होने से रह गए गांव काफी दूरदराज के और दुर्गम इलाकों के थे; उन तक साज-सामान और कर्मचारियों को पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन समग्र ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य दोनों तरीकों से हासिल किया गया- नेशनल ग्रिड से जोड़ कर भी, और उसके बगैर भी। ग्राम विद्युतीकरण का यह अर्थ नहीं है कि गांव के हरेक घर में बिजली पहुंच गई।

(जनसत्ता)

## महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

सरकार ने रविवार को कहा कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य मई 2017 तक पूरा किया जाना था, बहरहाल यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर गौर किया ही जाना चाहिए। कई स्तरों पर यह बहुत खेद की बात है कि देश के गांवों तक बिजली पहुंचाने में इतना अधिक वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उचित ही इसे प्राथमिकता में लिया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसके तहत गांवों तक बिजली पहुंचाने के काम को ऑनलाइन ट्रैक करना संभव हुआ।

सरकार ने इस दौरान काफी हद तक समय-सीमा का भी ध्यान रखा। यह काम आसान नहीं था। बल्कि यह काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि विद्युतीकरण के आखिरी दौर में उन गांवों तक बिजली पहुंचानी थी जो दूरदराज के इलाकों में थे और ऐसे पहाड़ी इलाकों में थे, जहां लोगों और सामग्री को पहुंचाना काफी मुश्किल काम था। ऐसे में इस उपलब्धि के लिए सरकार को बधाई देनी तो बनती है। परंतु फिर भी पूर्ण विद्युतीकरण की उपलब्धि का वह तात्पर्य नहीं है जो होना चाहिए। विद्युतीकरण की परिभाषा बेहद कमजोर है। इसके लिए गांव के आसपास बिजली का मूलभूत ढांचा उपलब्ध होना ही पर्याप्त है।

मसलन पंचायत कार्यालय में बिजली की व्यवस्था होना। इसके अलावा गांव के कम से कम 10 फीसदी परिवारों तक बिजली की पहुंच हो। इसमें सब तक पहुंच जैसी कोई बात नहीं है। न ही बिजली की उपलब्धता या निरंतर उपलब्धता से इसका कोई लेना-देना है। एक गांव को तब भी बिजली वाला माना जाएगा जब उसके आसपास से बिजली की लाइन गुजरती हो, पंचायत कार्यालय माइक्रो ग्रिड से संबद्ध हो और गांव के 10 फीसदी घरों में चंद घंटों के लिए ही बिजली आती हो। जाहिर सी बात है दूरदराज स्थित हर घर को ग्रिड से जोड़ने का काम अभी बाकी है। विभिन्न अनुमानों पर यकीन करें तो देश के 20 से 25 फीसदी घरों में अभी भी बिजली नहीं है। इसमें जो क्षेत्रवार अंतर है वह भी ध्यान देने लायक है।

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में जिन घरों में अभी बिजली पहुंचनी है उनकी तादाद नगण्य है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों में तकरीबन आधे घरों को अभी बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना बाकी है। अभी कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब 2.1 करोड़ परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की इस प्राप्ति को समय की कसौटी पर भी कसना होगा और इसकी पुष्टि करनी होगी।

(बिजनेस स्टैंडर्ड)

# राज्य में भाजपा को हराने का कांग्रेस में दम नहीं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 मई को भोपाल (मध्य प्रदेश) के भेल दशहरा ग्राउंड में आयोजित प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक में राज्य भर से आये मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का कांग्रेस में दम नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है जहां मां नर्मदा, मां क्षिप्रा का जल अहर्निश बहा करता है, जहां भगवान् महाकाल स्वयं विराज कर जगत के कल्याण का आशीर्वाद देते हैं और जहां बालक शंकर को शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिये एक तीर्थस्थान के समान है, यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता ने संगठन के मूल सिद्धांत के आदर्शों को चरितार्थ करने की धर्मयात्रा शुरू की थी और अपने जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण संगठन के विस्तार और पार्टी के विकास के लिये समर्पित कर दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि इस बार का चुनाव हम सबको मिलकर कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता के नाम समर्पित करना चाहिए और संगठन के आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजकल मैं लगातार कर्नाटक प्रवास पर रहता हूं, वहां विधान सभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन कर्नाटक की जनता से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे अपार समर्थन से यह तय है कि कर्नाटक में भी श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों का बयान देख रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कैसे? उन्होंने 2014 से 2018 तक की भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि शेख़चिल्ली का स्वप्न देख रहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि

आप में दम नहीं है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का।

श्री शाह ने कहा कि 2014 से 2018 तक का इस देश का राजनीतिक मानचित्र उठाकर देख लीजिये, 2014 में आजादी के बाद पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से आज तक देश में जितने भी चुनाव हुये हैं, उन सभी चुनावों में कांग्रेस हारी है और भाजपा को अभूतपूर्व जीत प्राप्त हुई है और जिस तरह से जनता का प्यार और आशीर्वाद देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा - हर जगह से कांग्रेस हारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि 15 मई को कर्नाटक विधान सभा चुनाव का भी परिणाम आने वाला है, वहां से भी कांग्रेस जायेगी और भाजपा आयेगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुये उन्होंने कहा कि राहुल जी, दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी कांग्रेस की विजय कहीं दिखाई नहीं देती, आखिर आपको स्वप्न आया कहां से? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहां भाजपा का संगठन अंगद का पांव है जिसे कोई डिगा नहीं सकता।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे सभी नेता अपने उद्बोधनों में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने कॉर्पोरेट घराने के प्रिय पात्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपना असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लड़ाई कॉर्पोरेट घराने और किसानों के बीच है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी किसानों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं कांग्रेस कॉर्पोरेट घराने का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राजा-महाराजाओं को लेकर चुनाव में उतरी है, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा हर एक बूथ कार्यकर्ता राजा-महाराजाओं को हराने की क्षमता रखता है।

श्री शाह ने कहा कि एक निरपेक्ष राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में मेरा विश्लेषण यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक जो कार्य किया है, वह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश की गिनती देश के 'बीमारू राज्यों' में हुआ करती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की सूची से निकल कर विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि श्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार सबसे ज्यादा कृषि विकास दर हासिल करने वाला राज्य बना है, सबसे ज्यादा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने वाला राज्य बना है। सबसे ज्यादा सड़कों का जाल बिछाने वाला राज्य बना है, सबसे ज्यादा विकास दर को प्रगतिशील रखने वाला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की उनकी पूरी मंत्रिमंडल और विधायकों की टीम ने मध्य प्रदेश के जन-जन का विश्वास जीतने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में विकास की गति को इसी तरह तीव्र बनाए रखनी है और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा कि हमें राज्य का अगला विधान सभा चुनाव जीतना है और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध होना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह चौहान सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। ■

# राकेश सिंह बने म.प्र. भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 अप्रैल को श्री राकेश सिंह, सांसद को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री राकेश सिंह ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान की जगह ली। श्री राकेश सिंह 2004 से जबलपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। 2014 में वे तीसरी बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए।

गत 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर श्री राकेश सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इस पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■

## संगठनात्मक नियुक्तियां

**भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 अप्रैल को मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, सांसद; भाजपा राजस्थान प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक परनामी, विधायक; भाजपा आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. हरीबाबू, सांसद को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य नियुक्त किया।**

# 'कार्यकर्ता भाव बना रहे'

भाजपा मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं। मध्यप्रदेश संगठन मनीषियों की कर्मभूमि है। जिसके कारण पूरे देश में मध्यप्रदेश के संगठन की पहचान एक आदर्श संगठन के रूप में हुई है। श्री कुशाभाऊ ठाकरे, श्री नानाजी, श्री सुंदरलाल पटवा जैसे वरिष्ठों की विरासत हमें मिली है। उस विरासत पर हमें गर्व होता है। भाजपा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भाव से कार्य करके जनमानस पर अमिट छाप अंकित करते हैं। यही हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है जो पार्टी के विस्तार पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बनाने में कामयाब हुई है। जिम्मेदारी और पद आते जाते हैं। यह मात्र एक प्रक्रिया है। इसका परिणाम तो हमें कार्यकर्ताओं के सहयोग और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मिशन 2018 की सफलता के रूप में मिलेगा। मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठन के रूप में प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुटना है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। कार्यकर्ता भाव बना रहे। इसके लिए हमें सतत संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। कार्यकर्ता होने का भाव हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर मतदान केन्द्र पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष की भावना के साथ जुटकर हमारा सहयोग करेगा और पार्टी अपने मिशन में सफल होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में चौथी बार सरकार और 2019 में पुनः श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनायेंगे। श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। मध्यप्रदेश में हमने जो चुनाव जीते हैं, उनमें कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ श्री नंदकुमार सिंह चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे भी उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा । ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

# अप्रैल 2018 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक

अप्रैल, 2018 में सकल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 1,03,458 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें 18652 करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 25704 करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 50548 करोड़ रुपये का आईजीएसटी (आयात पर संग्रहित 21246 करोड़ रुपये सहित) और 8554 करोड़ रुपये का उपकर या सेस (आयात पर संग्रहित 702 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। ऐसे 87.12 लाख लोगों के सापेक्ष 30 अप्रैल, 2018 तक मार्च महीने के लिए कुल मिलाकर 60.47 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए, जो मार्च महीने के लिए रिटर्न दाखिल करने के योग्य हैं और जो 69.5 प्रतिशत के आंकड़े को दर्शाता है।

अप्रैल महीने में कम्पोजीशन डीलरों को तिमाही रिटर्न भी दाखिल करने थे। 19.31 लाख कम्पोजीशन डीलरों में से 11.47 लाख डीलरों ने अपने-अपने तिमाही रिटर्न (जीएसटीआर 4) दाखिल कर दिए हैं, जो 59.40 प्रतिशत के आंकड़े को दर्शाता है। इन डीलरों ने कुल मिलाकर 579 करोड़ रुपये का टैक्स अदा किया है, जो 1.03 लाख करोड़ रुपये के उपर्युक्त कुल जीएसटी संग्रह में शामिल है।

जीएसटी राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में बेहतरी के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक अनुपालन को भी दर्शाती है। हालांकि, किसी भी वित्त वर्ष के अंतिम महीने में यह आम तौर पर पाया जाता है कि लोग कुछ विगत महीनों की बकाया रकम की भी अदायगी करते हैं। अतः उक्त महीने में हुए राजस्व संग्रह को भविष्य के लिए कोई रूझान नहीं माना जा सकता है। अप्रैल, 2018 में निपटान के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अर्जित राजस्व सीजीएसटी मद में 32493 करोड़ रुपये और एसजीएसटी मद में 40257 करोड़ रुपये आंका गया।

## अगस्त, 2017 से मार्च 2018 तक 7.19 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अगस्त 1, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कुल मिलाकर 7.19 लाख करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ। इसमें 1.19 लाख करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 1.72 लाख करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 3.66 लाख करोड़ रुपये का आईजीएसटी (आयात मद में 1.73 लाख करोड़ रुपये सहित) और 62,021 करोड़ रुपये का उपकर या सेस (आयात पर 5702 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। आठ महीनों की इस अवधि के दौरान औसत मासिक संग्रह 89,885 करोड़ रुपये का हुआ।

जहां एक ओर किसी एक महीने में घरेलू आपूर्ति पर देय टैक्स का संग्रह रिटर्न प्रक्रिया के जरिए होता है और इसका संग्रह अगले महीने होता है, वहीं दूसरी ओर आयात पर आईजीएसटी और उपकर का संग्रह समान महीने में हो जाता है। अतः चालू वर्ष के दौरान घरेलू आपूर्ति पर देय जीएसटी का संग्रह अगस्त, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक के आठ माह की अवधि में हुआ, जबकि आयात पर देय आईजीएसटी और उपकर का संग्रह जुलाई, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक के नौ महीने के लिए हुआ है। जुलाई 2017 के संग्रह को शामिल करने पर वित्त वर्ष 2017-18 में कुल जीएसटी संग्रह अनंतिम रूप से 7.41 लाख करोड़ रुपये आंका गया।

## राज्यों का राजस्व

आईजीएसटी के निपटान सहित वर्ष के दौरान एसजीएसटी संग्रह 2.91 लाख करोड़ रुपये का रहा है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान आठ माह की अवधि के लिए राज्यों को जारी कुल मुआवजा 41,147 करोड़ रुपये रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के राजस्व को वर्ष 2015-16 में आधार वर्ष के कर संग्रह की तुलना में 14 प्रतिशत के स्तर पर संरक्षित रखा जा सके। प्रत्येक राज्य का राजस्व अंतर पिछले आठ महीनों से निरंतर घट रहा है। पिछले वर्ष सभी राज्यों का औसत राजस्व अंतर लगभग 17 प्रतिशत रहा।

दरअसल, नियत तिथि तक अनुपालन स्तर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई और वित्त वर्ष के आखिर तक यह बढ़कर औसतन 65 प्रतिशत हो गया है, जबकि आरंभिक महीनों के दौरान यह लगभग 55-57 प्रतिशत था। आरंभिक महीनों के लिए संचयी अनुपालन स्तर (अब तक दाखिल रिटर्न का प्रतिशत) बढ़कर 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया और जुलाई 2018 के लिए यह बढ़कर 96 प्रतिशत के स्तर को छू गया है। ■

# प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मंडला में एक सार्वजनिक सभा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अगले पांच वर्ष के दौरान जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक रोडमैप का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने मंडला जिले के मनेरी में भारतीय रेल निगम के एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखीं। उन्होंने एक स्थानीय सरकारी डायरेक्टरी भी लांच की।

प्रधानमंत्री ने गांवों के उन सरपंचों का स्वागत किया, जिन्होंने शत-प्रतिशत धुआं रहित रसोइयों, मिशन इन्द्रधनुष के तहत शत-प्रतिशत टीकाकरण और सौभाग्य योजना के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है।

मध्य प्रदेश के मंडला में देशभर से आये पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय और ग्राम स्वराज को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश आकर वह खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा गांवों के महत्व पर जोर देते थे और ग्राम स्वराज की बातें किया करते थे। उन्होंने सभी लोगों से गांवों की सेवा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ग्रामीण विकास की बातें होती है, तो बजट महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में स्थितियां बदली हैं। लोग अब यह सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में बातें करने लगे है कि परियोजना के लिए आवंटित राशि का इस्तेमाल हो और योजना समय पर पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो। श्री मोदी ने लोगों से अपने बच्चों की पढ़ाई पर जोर देने का आग्रह किया और कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए यह आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कचरे को ऊर्जा में बदलने के अलावा वित्तीय समावेश के लिए जन-धन योजना, जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए वन-धन योजना और किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर-धन योजना के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गांवों में बदलाव से ही भारत की कायापलट को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये हाल के कदम महिला सुरक्षा की दिशा में लाभकारी होंगे। ■

# मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 21 अप्रैल को पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को स्वीकृति दे दी। यह योजना 7255.50 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 1.4.2018 से 31.3.2022 के दौरान लागू की जाएगी। योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 4500 करोड़ रुपये की होगी और राज्य की हिस्सेदारी 2755.50 करोड़ रुपये की होगी।

## मुख्य बातें–

(i) इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा और इसमें गैर-भाग IX में जहां पंचायतें नहीं हैं,ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान शामिल होंगे।

(ii) योजना में केंद्र और राज्य दोनों के घटक होंगे। केंद्रीय घटक में 'तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना, ई-पंचायत परमिशन मोड परियोजना और पंचायतों के प्रोत्साहन सहित राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां होंगी तथा राज्य घटक में पंचायती राज्य संस्थानों का क्षमता सृजन होगा।

(iii) केंद्रीय घटक का वित्त पोषण पूरी तरह भारत सरकार करेगी लेकिन राज्य घटक के लिए केंद्र-राज्य धन पोषण व्यवस्था सभी राज्यों के लिए 60:40 होगी। पूर्वोत्तर तथा पवर्तीय राज्यों में केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित और बिना विधानमंडल के) के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होगी।

(iv) सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के क्रियान्वयन और निगरानी गतिविधियों को सामान्य रूप से आपस में जोड़ा जाएगा और मुख्य बल मिशन अंत्योदय के अंतर्गत चिन्हित पंचायतों और नीति आयोग द्वारा चिंन्हित 115 आकांक्षी जिलों पर होगा।

(v) यह योजना अन्य मंत्रायलयों के क्षमता सृजन प्रयासों को मिलाएगी और उन मंत्रालयों पर फोकस किया जाएगा जिन पर इस योजना का अधिक प्रभाव होगा।

(vi) आरएसजीए की समाप्ति की तिथि 31.3.2030 होगी। ■

# मंत्रिमंडल ने 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' को जारी रखने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2 मई को कृषि क्षेत्र में छतरी योजना 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी। इसमें कुल केंद्रीय हिस्सा 33,269.976 करोड़ रुपये का है।

छतरी योजना में 11 योजनाएं/मिशन शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर तथा उत्पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्चत करके किसानों की आय बढ़ाना है। ये योजनाएं 33,269.976 करोड़ रुपये के व्यय के साथ तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जारी रहेंगी।

**छतरी योजनाओं के हिस्से के रूप में निम्न प्रमुख योजनाएं हैं:**

- बागबानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)– 7533.04 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय हिस्से के साथ एमआईडीएच का उद्देश्य बागबानी उत्पादन बढ़ाकर, आहार सुरक्षा में सुधार करके तथा कृषि परिवारों को आय समर्थन देकर बागबानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।
- तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में कुल केंद्रीय हिस्सा 6893.38 करोड़ रुपये का है। इसका उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेंहू, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। यह कार्य व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता बहाल करके और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाकर किया जाएगा। इसका एक और उद्देश्य खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना और खाद्य तेलों के आयात को घटाना है ।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) में 3980.82 करोड़ रुपये का कुल केंद्रीय हिस्सा है। एनएमएसए का उद्देश्य विशेष कृषि परिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के मेलजोल से सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है।
- 2961.26 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय हिस्से के साथ कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमएई) का उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि की जारी विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है, ताकि कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था संस्थागत बनाई जा सके, विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपायों को नवाचारी बनाया जा सके। ■

# सरकार ने तीन वर्षों के लिए कुल 2,500 मेगावॉट की ऊर्जा खरीद की पायलट योजना लॉन्च की

केन्द्रीय सरकार ने मध्यम अवधि के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए कुल 2,500 मेगावॉट की ऊर्जा खरीद की पायलट योजना को लॉन्च किया। यह योजना उन विद्युत उत्पादकों के लिए है जिनकी परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी है, परन्तु उनके साथ ऊर्जा खरीद समझौता नहीं किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में 06 अप्रैल, 2018 को मॉडल निविदा प्रपत्र, मॉडल पीएपीपी और मॉडल पीपीएसए जारी किया है। इस योजना के लिए 10 अप्रैल, 2018 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को नोडल एजेंसी तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड को एग्रीगेटर नियुक्त किया गया है। पीटीसी इंडिया, ऊर्जा खरीद के लिए सफल निविदाकर्ताओं के साथ तीन वर्षों (मध्यम अवधि) का ऊर्जा खरीद समझौता और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ विद्युत आपूर्ति का समझौता करेगी।

इस योजना के तहत एक कंपनी को अधिकतम 600 मेगावॉट की ऊर्जा क्षमता आवंटित की जा सकती है। यह योजना, समझौता क्षमता के 55 प्रतिशत खरीद का आश्वासन देती है। तीन वर्षों के लिए ऊर्जा की दर निश्चित रहेगी और इसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पीएफसी सी. लिमिटेड इस योजना के अंतर्गत मई 2018 के प्रथम सप्ताह तक निविदा आमंत्रित करेगी। निविदा की प्रक्रिया डीईईपी ई-बिडिंग पोर्टल पर संचालित की जाएगी। आशा है कि यह योजना ऊर्जा मांग को पुनर्जीवित करेगी। ऊर्जा की मांग में कमी ने उन बिजली उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिनके साथ ऊर्जा खरीद समझौता नहीं किया गया है। ■

# भारतीय संस्कृति में अर्थ

| दीनदयाल उपाध्याय |

## शेष...

## सर्वांगीण दृष्टिकोण की आवश्यकता

पाश्चात्य अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं, वे एक अर्थपरायण व्यक्ति (Economic man) की कल्पना करके चलते हैं। यह अर्थमापी व्यक्ति जीवन में कहीं नहीं मिलता। स्वयं जे.एस. मिल ने माना है-"संभवतः कोई भी व्यावहारिक प्रश्न ऐसा नहीं होता, जिसका निर्णय आर्थिक सीमाओं के अंदर ही दिया जा सके। अनेक आर्थिक प्रश्नों के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक पहलू होते हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।'' किसी समय विशेष पर मानव व्यवहार जीवन के अनेक मूल्यों के आकर्षण-विकर्षण से निश्चित होता है। विभिन्न शास्त्रों के विद्वान् उसी एक व्यवहार का विश्लेषण अपने-अपने दृष्टिकोण से करते हैं। वे एक ऐसी स्थिति की कल्पना करके चलते हैं, जिसमें अन्य प्रवृत्तियों का अस्तित्व न हो। किंतु उनके काल्पनिक जगत् और व्यवहार जगत् में सदैव ही बहुत बड़ा अंतर रहता है। उनके सिद्धांत सही भी हों तो भी सीमित उपयोग के रहते हैं।

## चार पुरुषार्थ

भारत ने इसीलिए मनुष्य का विभाजित विचार न करके पूर्णता के साथ विचार किया। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का चार मोटे-मोटे भागों में वर्गीकरण करके उन सबकी संतृप्ति ही मानव का पुरुषार्थ बताया। ये चार पुरुषार्थ हैं : धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों एक-दूसरे के पूरक हैं। जो कर्म इन सबको प्राप्त कराने वाला हो, वही श्रेष्ठ है। इनमें से किसी की भी अवहेलना करके चलने वाला व्यक्ति दुःख और अशांति का भागी बनता है।

इन चारों में से किसी एक को भी श्रेष्ठ या शेष का आधार समझना भी ठीक नहीं होगा। वैसे मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्तव्य नहीं बच रहता। किंतु बिना धर्म, अर्थ और काम के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, "धर्मादर्थश्चकामश्च,' अर्थात् धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। जहां कोई व्यवस्था ही नहीं, वहां अर्थ और काम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किंतु दूसरी ओर हमने इसका पूर्व विवेचन किया है कि किस प्रकार अर्थ के बिना धर्म नहीं टिक पाता। वास्तव में ये चारों पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित हैं। एक से दूसरे की रक्षा और संवर्धन होता है।

जिस प्रकार प्राण अन्न से बलवान होते हैं तथा सबल प्राण अन्न को पचा सकते हैं, वैसे ही धर्म से अर्थ और काम की तथा अर्थ और काम से धर्म की धारणा होती है।

## चार विद्याएं

इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली विद्याओं के संबंध में विवेचन करते हुए भी कौटिल्य ने लिखा है: 'आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या।'' आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार विद्याएं हैं। इसके पूर्वाचार्यों ने इनमें से किसी एक, दो या तीन को ही विद्या माना] किंतु कौटिल्य ने चारों को मान्यता दी। उन्होंने लिखा''चनस्त्र एवं विद्या कौटिल्य। तामिर्धर्मार्थीयद्विद्यात्तद्विद्यानां विद्यात्वम्।' अर्थात् कौटिल्य के मत से चारों ही विद्या हैं, जिनसे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है, वे वास्तव में विद्या हैं और उन्हें उस रूप में मानना चाहिए।

मनुष्य के जीवन का यह सर्वांगपूर्ण विचार ऐसी किसी भी अर्थ-रचना की कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना किए बिना ही मनुष्य को सुखी बनाया जा सके। इतना ही नहीं, कोई भी अर्थ-रचना अपनी सफलता और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक इच्छा, उत्साह और सामर्थ्य का सृजन स्वयं नहीं कर सकती। अपनी ही गति से बराबर गतिमान अर्थव्यवस्था असंभव है। उसे गति देने के लिए और बाद में भी कम-से-कम रुकावट के साथ सुचारु रूप से चलते रहने के लिए व्यक्ति और समाज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत अर्थ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ढूंढ़ना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं अर्थ-रचना को बनाने और टिकाने में सहायक होती हैं। अतः हम समाज या व्यक्ति की समस्याओं एवं उसके लक्ष्यों का टुकड़ों में विचार नहीं सकते। यह हो सकता है कि समय विशेष पर हम किसी एक अंग को अधिक महत्त्व दें] किंतु हम शेष की भी अवहेलना नहीं कर सकते। ■ (समाप्त)

('भारतीय अर्थ-नीति विकास की एक दिशा' से साभार)

# के. जना कृष्णमूर्ति

## (24 मई 1928 –25 सितंबर 2007)

श्री के. जना कृष्णमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर राष्ट्रप्रेमी और कुशल राजनेता थे। वे 2001 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। श्री जना कृष्णमूर्ति श्री कामराज के बाद तमिलनाडु से आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व किया।

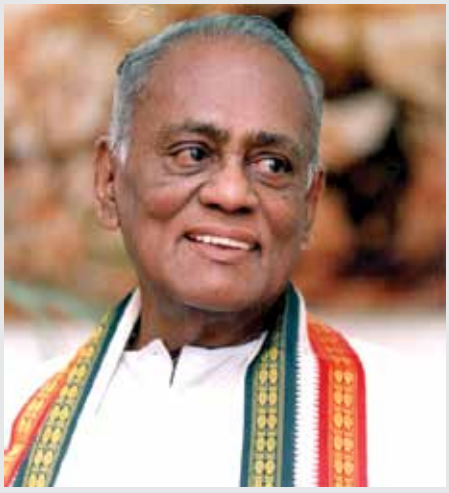

श्री कृष्णमूर्ति का जन्म 24 मई 1928 को तमिलनाडु राज्य के मदुरई में हुआ। उनके पिता और माता का नाम श्री कृष्णास्वामी और श्रीमती सुब्बलक्ष्मी था। उन्होंने 1965 में सफल वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री एम. एस. गोलवलकर की प्रेरणा से राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। दरअसल, श्री कृष्णमूर्ति 1940 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक थे। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनसंघ के महामंत्री का कार्य भार संभाला। सच तो यह है कि श्री कृष्णमूर्ति दक्षिण भारत में भारतीय जनसंघ को मजबूत और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ, तो उस समय वह तमिलनाडु में संघर्ष समिति के सचिव थे। 1977 में जब भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, तब वह पार्टी की तमिलनाडु ईकाई में महामंत्री बने। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री कुशाभाउ ठाकरे और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय सचिव थे। 1983 में वे राष्ट्रीय महामंत्री बने और 1985 में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 1980 से 1990 के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के चार राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भाजपा के विस्तार में अतुलनीय योगदान दिया।

1993 में श्री लालकृष्ण आडवाणी के अनुरोध पर वे दिल्ली आ गए और भाजपा में आर्थिक, रक्षा और विदेशी मामलों पर बौद्धिक प्रकोष्ठ की स्थापना की। 1995 में वे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के प्रभारी बने। उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पद को भी सुशोभित किया। 14 मार्च 2001 को वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जून 2002 तक वे इस पद पर रहे। इसके साथ ही श्री जना कृष्णमूर्ति अप्रैल 2002 में राज्यसभा के सदस्य बने और 2002-2003 तक केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे। 25 सितबंर 2007 को श्री जना कृष्णमूर्ति का देहावसान हो गया। राष्ट्र और भाजपा इनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ है। ■

# कर्नाटक भाजपा विधायक बी. एन. विजय कुमार नहीं रहे

कर्नाटक भाजपा विधायक श्री बीएन विजय कुमार का 3 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया। जयनगर विधानसभा सीट से विधायक श्री विजय कुमार 59 वर्ष के थे और वे कर्नाटक में 12 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी थे। वे जयनगर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं।

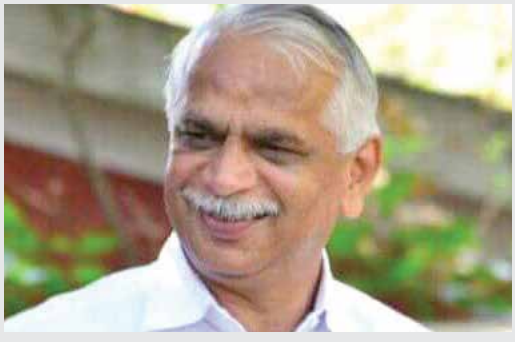

श्री विजय कुमार पट्टाभीरामनगर में डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे थे। उन्हें लंबे समय से हाई ब्लडप्रेर की समस्या थी। हाल ही में उनका जयदेवा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। कुछ दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी। हालांकि, उन्होंने इस सलाह को नहीं माना और प्रचार अभियान में यह कहते हुए जुट गए कि अब चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है।

श्री कुमार को उनकी ईमानदार छवि व विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। श्री विजय कुमार 1980 में भाजपा में आए और बेहद विनम्र व जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे। कर्नाटक राज्य के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "मैं अपने दोस्त और पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार के असामयिक निधन से बहुत दुखी हूं।" ■

# श्रमिकों को 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से जोड़ने की आवश्यकता : नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अभिनव तरीकों के साथ काम करने का आह्वान किया। एक मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिकों को 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से जोड़ने की आवश्यकता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष गंगवार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर श्रमिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हमारे मंत्रालय और केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

श्री गडकरी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम आयुक्त (सीएलसी) द्वारा प्रारंभ की गई नई पहलों का शुभारंभ किया तथा ईएसआईसी और ईपीएफओ को आदर्श नियोक्ताओं का पुरस्कार प्रदान किया। नई पहलों में ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए समवर्ती लेखा सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके तहत भुगतान, प्राप्तियां और दावों के निपटारे, पेंशन के भुगतान, पीएफ संचय के हस्तांतरण आदि लेन-देन वास्तविक समय पर किए जा सकेंगे।

यही नहीं, भविष्य निधि भवन, मालवीय नगर, नई दिल्ली की पुनर्विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। पुनर्विकास परियोजना की अनुमानित लागत 22.47 करोड़ रुपये है और कार्य पूरे होने की अनुमानित अवधि 22 महीने है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेट लाईफ ग्लोबल ऑपरेशंस स्पोर्ट सेंटर और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड को छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में मॉडल नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (वीपी/बीआरडी/5238) को गैर छूट वाले क्षेत्र में सम्मानित किया गया। गैर-छूट वाले क्षेत्र में दो नियोक्ता ऐसे हैं, जिनके पास 5000 से अधिक कर्मचारी हैं और जिन्होंने पिछले 12 महीनों में भविष्य निधि बकाया रकम का समय पर भुगतान किया है और 'आधार' सत्यापित कर्मचारी विवरण प्रदान करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का चयन उनके ऑनलाइन रिटर्न डैशबोर्ड में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया गया है। चयनित किए गए प्रतिष्ठान ने ऑनलाइन रैंकिंग प्रणाली में पिछले 7 महीने में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। सीएलसी ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है जैसे श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) पर 8 श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, एसएसपी के माध्यम से निरीक्षण की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम 1979 तथा अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना आदि।

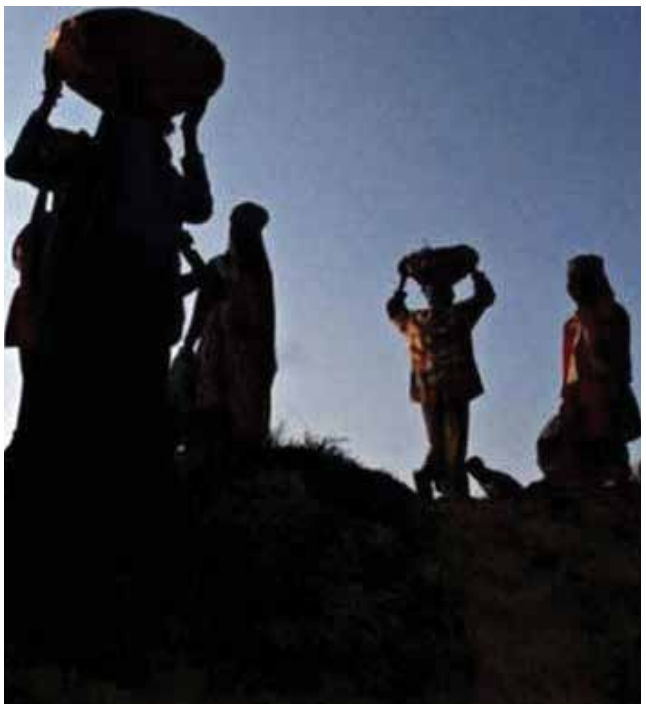

ईएसआईसी ने मैसर्स लेप्रोसी मिशन कम्युनिटी हॉस्पिटल, नंदनगरी, दिल्ली, वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड वापी, गुजरात और मैसर्स लुकास टीवीएस पुडुचेरी को मॉडल नियोक्ता के रूप में चयन किया। इन प्रतिष्ठानों ने समय पर योगदान का भुगतान किया है और 100% योग्य कर्मचारियों को कवर किया है।

साथ ही, श्री गडकरी ने एक न्यूजलेटर "चाइल्ड होप" भी जारी किया। इसमें पूरे देश के एनसीएलपी जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों की सफल कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख किया जाता है। "चाइल्ड होप" का उद्देश्य बाल श्रम से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाना है। इस अवसर पर वीवीजीएनएलआई पॉलिसी परिप्रेक्ष्य भी जारी किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ■

कर्नाटक के भाजपा उम्मीदवारों, जन–प्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद

# हम विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं: नरेन्द्र मोदी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव-प्रचार में जोर-शोर से जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बी.एस. येदियुरप्पा धुंआधार प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के 223 सीटों के लिए मतदान 12 मई को होने हैं और और 15 मई को परिणाम आने हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राज्य के भारतीय जनता पार्टी के पार्टी पदाधिकारियों, उम्मीदवारों, चुने हुए जन-प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से नरेन्द्र मोदी एप के माध्यम से वीडियो ब्रिज तकनीक के जरिये सीधा संवाद किया। श्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का भाग्य बदलने के लिए भाजपा का तीन सूत्रीय एजेंडा है– "विकास, विकास और विकास" और हम विकास की राजनीति को ही प्राथमिकता देते हैं।

वीडियो ब्रिज में भाजपा की नेतृत्व वाली भारत सरकार की कर्नाटक के सर्वांगीण विकास के लिए चार साल की अनेक उपलब्धियों की तुलना UPA सरकार के अंतिम चार साल से करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि UPA सरकार विकास के नाम पर जनता को गुमराह करके और झूठे वादों का लॉलीपॉप दिखा कर चुनाव में उतरती थी। वह हर चुनाव में समाज के किसी एक वर्ग समूह को झूठे वादों का लॉलीपॉप दिखाती थी, फिर चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाती थी, यही कांग्रेस का कल्चर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुकृत्यों के कारण देश की राजनीति में तमाम बुराईयां आ गईं, हमें राजनीति को कांग्रेस के इस कल्चर से मुक्त कर के भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण करना है। उन्होंने कहा कि हम जनता को गुमराह करके नहीं, बल्कि विकास करके जनता का दिल जीतना चाहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज में जातिवाद का

जहर घोल कर और समाज में फूट डालकर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति की है जबकि हम हमेशा 'सबका साथ सबक विकास' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का सपना लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पराजय निश्चित है, इसलिए झूठा दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह किया जा रहा कि कर्नाटक में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मतदाता जागरूक हैं और राज्य में परिवर्तन लाने के लिए वे भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश देंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जाति-धर्म की राजनीति के बजाय जनता को विकास की राजनीति से ही मतलब है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की जनता ने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए भाजपा को जनादेश दिया और वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने सभी नीतिगत निर्णय, देश के विकास और जनता के हित में लिए हैं।

श्री मोदी ने बिंदुवार कर्नाटक में केंद्र सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रही है। कर्नाटक में सड़क निर्माण के विकास की UPA के कार्यकाल और NDA सरकार के 4 साल के काम की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि UPA के समय में करीब 8,700 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था, जबकि हमने 14,000 करोड़ रुपयों के 13 बड़े सड़क प्रोजेक्ट शुरू किये हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर भी UPA के चार साल में लगभग 950 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे जबकि हमने चार साल में 1750 करोड़ का अर्थात् लगभग दोगुना काम किया है। उन्होंने कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी UPA के चार साल में महज 380 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था जो हमारे कार्यकाल में चार गुना बढ़कर 1600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

श्री मोदी ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कांग्रेस जहां 2,000 मेगावाट कैपेसिटी ही विकसित कर पाई थी, वहीं हमने चार साल में 7,800 मेगावाट यानी करीब चार गुना कैपेसिटी विकसित की है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कांग्रेस की उदासीनता का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि UPA के चार साल में सिर्फ 31 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट्स स्थापित हुए थे जबकि हमने कर्नाटक में 4,800 मेगावाट सोलर पॉवर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स स्थापित किये हैं।

## हम देश को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने को कृतसंकल्पित हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 मई को कर्नाटक के तुमकुरु, गडग और शिवमोगा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कर्नाटक के चहुंमुखी विकास के लिये राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की विकासोन्मुखी येदुरप्पा सरकार बनाने की अपील करते हुये भ्रष्टाचारी सिद्धारमैया सरकार पर जमकर हमला बोला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आधुनिक, प्रगतिशील और विकासशील कर्नाटक का सपना लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की हमारी सरकार ने कर्नाटक के विकास और राज्य की आम जनता के कल्याण के लिये कई कदम उठाये हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की ऐसी सरकार बैठी हुई है जो सोती रहती है, वह जन-कल्याण की योजनाओं को राज्य की जनता तक पहुंचने ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि हमने आधार के साथ डीबीटी योजना शुरू की और सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके परिणाम धरातल पर दिखने शुरू हो गये हैं। उन्होंने कहा कि हमने कृषि सिंचित भूमि का रकबा बढ़ाया है, खेत से लेकर खलिहान तक फसल को सुरक्षित करने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिये स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है और नीम कोटिंग यूरिया के द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की वर्तमान मुश्किलें कांग्रेस की पुरानी नीतियों के कारण हैं और तिसपर भी कांग्रेस किसानों के कर्ज पर राजनीति करने से बाज नहीं आती।

श्री मोदी ने कहा कि आगामी 15 मई, 2018 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, बल्कि यह पीपीपी कांग्रेस अर्थात् पंजाब, पुद्दुच्चेरी, परिवार कांग्रेस बन जायेगी और कांग्रेस पार्टी को पीपीपी कांग्रेस पार्टी बनाने का काम भी कर्नाटक की जनता करेगी।

श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के लिए तो केवल एक ही मंत्र है 'बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया' और मुख्यमंत्री जी ने तो कहावत ही बदल दी उनका मंत्र है 'बाप भी बड़ा, भैया भी

### प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों के सवालों के जवाब भी दिए, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –

- हमें राज्य के हर एक मतदाता तक पहुंचना है, उनका दिल और विश्वास जीतना है। जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा।
- कर्नाटक के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की काफी संभावना है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की जाति-पाति की राजनीति राज्य के विकास में रुकावट बनी हुई है।
- कर्नाटक में भी शहरीकरण तेजी से हो रहा है और गांवों से लोग रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसे में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार विकास करने से कतराती है।
- कर्नाटक में मेरा एक ही अजेंडा है- डिवेलपमेंट, फास्ट पेस डिवेलपमेंट, ऑल राउंड डिवेलपमेंट।

बड़ा मगर उससे भी बड़ा रुपैया, सिद्धा रुपैया'। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जबकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है हम देश को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि Congress के 'C' और Corruption के 'C' में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता नोटबंदी को लेकर आज भी रोते हैं, देश की जनता को याद होगा कि नोटबंदी के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के कैसे-कैसे दिग्गजों के घर से भर-भर के नोट बरामद हुये थे। उन्होंने कहा कि मीडिया के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता की संपत्ति कुछ ही वर्षों में 75 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ रुपये हो गई। आखिर ये पैसा आया कहां से? उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में जितने भी चुनाव हुये, लगभग उन सभी चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय - सब हारती चली गई है, देश के हर कोने में जनता ने कांग्रेस को साफ कर दिया है और अब बारी कर्नाटक की है, कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी का सफाया होना तय है।

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुये श्री मोदी ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि हेमवती नदी का पानी हमारे तुमकुर के किसानों को क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हम हेमवती और नेत्रावती नदी को जोड़कर टुमकुर और आसपास के 8 जिलों के किसानों तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। उन्होंने भद्रा प्रॉजेक्ट जैसी अधूरी सिंचाई योजनाओं का जिक्र कर सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों को जोड़ने के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 महीनों में हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर किसानों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने दुनिया के बाजारों में हमारे कृषि उत्पादों को भेजा होता तो आज हमारे किसानों की यह हालत न होती। उन्होंने सिद्धारमैया से प्रश्न पूछते हुये कहा कि सिद्धारमैया जी गडग के लोगों को गुमराह करने से पहले जरा मैडम सोनिया से पूछ लेते कि महादायी के लिए कांग्रेस की नीति क्या है क्योंकि 2007 में सोनिया जी ने कहा था कि महादायी का पानी कर्नाटक को न मिले इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक का विकास नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर्नाटक को राज्य में सात स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 836 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार अब तक केवल 12 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि कर्नाटक के कई हिस्से बिजली के लिए अब भी तरस रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इन क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाने का प्रबंध किया है।

कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम सर्वेक्षणों में जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) राज्य में तीसरे नंबर पर रहने वाली है। ऐसे में कर्नाटक की जनता जेडीएस को अपना वोट देकर खराब न करे क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सिद्धारमैया सरकार को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच पर्दे के पीछे सांठ-गांठ है। बेंगलुरु कॉर्पोरेशन में तो जेडीएस के समर्थन से कांग्रेस का मेयर भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत होनी चाहिए कि वह जेडीएस से अपना नाता स्वीकार करे और लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री एच डी देवेगौड़ा जी ने घोषणा की थी कि मोदी के जीतने पर मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैंने उस समय भी उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव कभी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं श्री एचडी देवगौड़ा की बड़ी इज्जत करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा सरकार स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड-अप और स्टार्ट-अप योजनाओं के जरिये युवाओं को रोजगार देने की दिशा में विशेष प्रयास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि केंद्र की हमारी सरकार ने इतने कम समय में ही लगभग चार करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया है, कर्नाटक में भी लाखों महिलाओं को इसका फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को गरीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि अपना नाम चिपकाने की चिंता थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और जब कर्नाटक का विकास होगा, तभी देश का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अकेले कर्नाटक में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के रेलवे की योजनायें चल रही है। उन्होंने कहा कि हम विकास के प्रति समर्पित हैं और हम श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने कर्नाटक की जनता से अपील करते हुए कर्नाटक के ग्रोथ इंजन को एक बार फिर तेज करने और स्वस्थ, सुन्दर और सुरक्षित कर्नाटक के निर्माण के लिए आगामी 12 मई, 2018 को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

## 'कांग्रेस पार्टी न तो दिलवाली है, न दलितोंवाली, केवल डीलवाली है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 मई को कर्नाटक के चित्रदुर्ग, रायचूर और जमखंडी में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और कर्नाटक की जनता को विकास से वंचित रखने का पाप करने के लिये कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आज जनसभाओं की शुरुआत चित्रदुर्ग से करते हुये चंद्रयान मिशन में लगे सभी वैज्ञानिकों और टेक्निशियनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यहां की धरती 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान'

के मंत्र की पर्याय है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय वीरों और वीरांगनाओं का सम्मान करने की जगह सुल्तानों का सम्मान कर कर्नाटक की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की खातिर, कांग्रेस का चरित्र देखिए कि जिसकी जयंती मनानी चाहिए, उसकी तो मनाते नहीं हैं, वीर मदकरी नायक, वीरा मरकडी, वीर कवि कुवेम्पु को तो भुला दिया, लेकिन सुल्तानों की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे वोटबैंक की राजनीति के लिए इतिहास और भवनाओं को मरोड़कर आगे बढ़ने की आदत हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो दिलवाली है और न दलितोंवाली है, ये केवल डीलवाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को राज्य की जनता के वेलफेयर की कोई चिंता ही नहीं है, जो कांग्रेस आपके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, अब उनके फेयरवेल करने का वक्त आ गया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश की धरती से जुड़े रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को परिनिर्वाण के बाद भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, यह भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके समर्थन से केंद्र में बनने वाली सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया। उन्होंने कहा कि हजारों योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर हैं दिल्ली में सभी स्मारक एक ही परिवार के नाम पर हैं, मकान और जमीन पर एक ही परिवार का कब्जा है, लेकिन बाबा साहेब के लिए स्मारक बनाने के लिए कांग्रेस कभी आगे नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने बाबा साहेब की जयंती दुनिया भर में मनाई। उन्होंने कहा कि मऊ में बाबा साहेब की जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में कर्म भूमि पर हमारी सरकार ने काम किया। उन्होंने कहा कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया और जब दूसरी बार केंद्र में हमारी सरकार आई तो हमने गरीब दलित परिवार में पैदा हुये श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दलितों के प्रति नफरत देखिये कि श्री रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद से आज तक कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने शिष्टाचार भेंट तक नहीं की है, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके राष्ट्रपति बनने के सात महीने बाद उनसे मिले थे, वह भी ज्ञापन सौंपने गये थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिये कोई काम ही नहीं किया, यही कारण है कि वह आज भी दलितों के नाम पर देश को भटका रही है, दलित और गरीब अगर कांग्रेस की प्राथमिकता होते तो आज उन्हें दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने कहा कि दलित कल्याण के नाम पर यहां के एक मंत्री ने अपने कल्याण की योजना कैसे बनाई? ये कर्नाटक के लोग भलीभांति जानते हैं, गंगा कल्याण के नाम पर इन्होंने खुद का कल्याण किया। उन्होंने सभा में उपस्थिति जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार तो जनता के पानी के पैसे भी खा गई, आदिवासियों के हॉस्टल में बिस्तर लगाने के पैसे भी खा गई, चादर, तकिया तक के पैसे भी खा गई, कहीं ऐसा न हो कि आपके घर के बिस्तर के पैसे भी खा जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कांग्रेस को और भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गरीब और पिछड़ी जाति से आता है और महामहिम राष्ट्रपति जी भी दलित परिवार से आते हैं, इसलिए कांग्रेस ने दलितों में भ्रम और झूठ फैलाने का अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद हमने एससी/एसटी ऐक्ट को और कड़ा कर दिया, ताकि दलितों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलितों, गरीबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी भलाई के काम करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भाषा, जाति, पंथ के नाम पर कर्नाटक को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' के नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े होने भी देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति समर्पित है तो कांग्रेस विकास के विरोध में है। भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' सोचती है तो कांग्रेस एक ही परिवार के लिए सब कुछ करना चाहती है। भाजपा भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है तो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि यहां के मुख्यमंत्री तो सूटकेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिये घूमते हैं, अपनी सरकार के किसी मंत्री अथवा नेता पर आरोप लगा नहीं कि वे तुरंत उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। उन्होंने कर्नाटक की जनता से अपील करते हुये कहा कि भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री को क्लीन स्वीप कर दीजिये।

श्री मोदी ने कहा कि हम किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं, कांग्रेस झूठे वादे करने वाली पार्टी है, 'बांटो और राज करो' वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिल्ली के नेता हों या गली के नेता, वे सिर्फ आरोप लगाते हैं ये लोग दिन-रात मोदी-मोदी-मोदी-मोदी करते रहते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी वादे का हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से कांग्रेस चली गई, कर्नाटक से भी इनका सफाया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नया मंत्र है- झूठ बोलो, जहां बोल सकते हो, जितना बोल सकते हो, झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो। श्री मोदी ने कहा, "हम कर्नाटक को कांग्रेस द्वारा बंटने नहीं देंगे, यहां जातिवाद का जहर नहीं घुलने देंगे। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन कर्नाटक को टूटना नहीं चाहिए। कांग्रेस कर्नाटक को बांटने में लगी है लेकिन उसे हम ऐसा नहीं करने देंगे। 12 मार्च को अलगाववाद का खेल करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखाएगी।" उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपनी निश्चित हार की डर से बिना बताये बादामी चले गए लेकिन वहां भी जनता उनके कारनामों को माफ़ नहीं करेगी। ■

# पिछले पांच वर्षों से कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार से विकास नहीं हो पायाः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 अप्रैल को कर्नाटक के कोप्पल जिले के कुक्कानूर (येलबुर्गा विधानसभा क्षेत्र) और गंगावती में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़कर श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने कहा कि आगामी 15 मई को कर्नाटक से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार जाने वाली है और श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक में विकास के एक नये युग की शुरुआत होने वाली है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक की रैलियों में कहते हैं कि राज्य में फिर से सिद्धारमैया सरकार आएगी, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि देश में 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग उन सभी चुनावों में कांग्रेस हारी है और भाजपा को अभूतपूर्व जीत मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल जी, तनिक आप इतिहास पर भी नजरें दौड़ा लीजिये, आपने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, देश में से कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता सिद्धारमैया सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इसलिए उन्होंने सिद्धारमैया सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन राज्य का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने पूरे कर्नाटक को विकास से वंचित रखने का पाप किया है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया जी, इन पांच सालों की आपकी सरकार में आपका तो विकास हुआ, लेकिन कर्नाटक का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब से सिद्धारमैया सरकार आई है, राज्य में किसानों की आत्महत्या में लगभग 173% की बढ़ोत्तरी हुई है, पिछले पांच सालों में राज्य में लगभग 3500 से अधिक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के पिछले चार सालों में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 24 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी रही और हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सिद्धारमैया को चुनौती देते हुए कहा कि सिद्धारमैया जी, आप हत्यारों को जितना भी छुपाना चाहो लेकिन वे बचेंगे नहीं। राज्य में येदुरप्पा सरकार के बनते ही हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सिद्धारमैया पर हमला जारी रखते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए आप हत्यारों के साथ हाथ मिलाते हैं, गठबंधन करते हैं, कर्नाटक की जनता कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस ने SDPI जैसी हत्यारी पार्टी के साथ समझौता किया है, जो पार्टी ऐसे संगठन के साथ गठबंधन करती है, उसे कर्नाटक में शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में केवल 1% किसानों को ही सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप एक बार राज्य में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिये, हम पूरे कर्नाटक में किसानों के लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2022 तक कोप्पल जिले को अकाल-मुक्त कर यहां के किसानों की आमदनी को दुगुना करने की व्यवस्था की जायेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कर्नाटक के विकास के लिए कई कदम उठाये गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग में केन्द्रीय अनुदान के रूप में कर्नाटक के लिए 2,19,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, जबकि लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है जो किसानों की आय को दुगुना करने में एक क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो गरीबों को काफी राहत पहुंचाने वाला है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक का विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पांच सालों में सिद्धारमैया सरकार न तो गांवों में बिजली पहुंचा पाई, न किसानों को फसल के उचित मूल्य दे पाई और न युवाओं को रोजगार ही मुहैया कर पाई। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है, महिलायें असुरक्षित हैं और किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, यही सिद्धारमैया सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की जनता से प्रश्न पूछते हुए कहा कि आपको कर्नाटक में विकास के प्रति कमिटेड येदुरप्पा सरकार चाहिए या फिर कमीशन लेने वाली सिद्धारमैया सरकार? यदि आपको कमिटेड सरकार चाहिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में येदुरप्पा सरकार का गठन कीजिये, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अगले पांच सालों में कर्नाटक को विकास में देश के मॉडल स्टेट के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे।

**कोलार गोल्ड फील्ड्स**

## सिद्धारमैया सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ भी नहीं किया है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स (केजीएफ विधानसभा) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से कर्नाटक के विकास के लिए पूर्ण बहुमत की येदुरप्पा सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने चारा घोटाले के कई मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव से राहुल गांधी की मुलाक़ात पर करारा प्रहार किया और कहा कि इस मुलाक़ात ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को देश की जनता के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी सोनिया-मनमोहन सरकार लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त राहुल गांधी ने जनता के सामने दिखावा करते हुए अध्यादेश की कॉपी फाड़ने का नाटक किया था। अब जब 2019 का चुनाव आ रहा है तो राहुल गांधी को डर लग रहा है कि लालू यादव की मदद के बिना वे चुनाव में अपनी इज्जत भी नहीं बचा पायेंगे, तो वही अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी आज चारा घोटाले के कई मामलों में सजा पा चुके कैदी लालू यादव से मिलने पहुंच जाते हैं और उन्हें गले लगाकर सरकार बनाने की जुगाड़ में लगे हैं।

राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस एक घटना ने देश की जनता के सामने राहुल गांधी के दो चेहरों को उजागर किया है - जब सत्ता में होते हैं तो किस प्रकार का चाल, चरित्र और चेहरा होता है और जब सत्ता में नहीं होते हैं, सत्ता प्राप्त करनी होती है तब लालू जी को भी गले लगाने से नहीं हिचकिचाते। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस पार्टी के इस प्रकार के दोहरे मापदंड हो, वह पार्टी कर्नाटक में साफ़-सुथरी सरकार कतई नहीं दे सकती।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के दौरान 10 वर्षों में अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले हुए थे और देश के खजाने को जमकर लूटा गया था। आज राहुल गांधी लालू यादव से मिलकर देश की जनता को कांग्रेस की यूपीए सरकार के उसी दौर को याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से बेल पर चल रहे हों, उस पार्टी से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावे कुछ और की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और इतिहास गवाह है कि आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की चार पीढ़ियों के 70 साल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने लोगों की भलाई करने के बजाय केवल एक परिवार का भला किया है। सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में विगत पांच वर्षों के शासनकाल में सिद्धारमैया सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोई सरकार विद्युत आपूर्ति में नंबर वन बनती है, कोई गरीबों के आवास बनाने में नंबर वन बनती है, कोई रोजगार प्रदान करने में नंबर वन बनती है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार करने में नंबर वन आई है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मुखिया ही भ्रष्टाचार का समर्थक हो, उस पार्टी की सरकार ऐसे ही चलती है।

**शृंगेरी एवं मुदिगेरे (चिकमंगलूर) और अरकलागुदु (हासन)**

## लोगों ने भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 मई को कर्नाटक के शृंगेरी एवं मुदिगेरे (चिकमंगलूर) और हासन के अरकलागुदु में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से कर्नाटक को मॉडल स्टेट बनाने के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की येदुरप्पा सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने राज्य में सुपारी और कॉफी उत्पादक किसानों की

समस्याओं का जिक्र करते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने सुपारी और कॉफी उत्पादक किसानों की भलाई के लिये कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि पहले सुपारी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल 163 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ा कर 251 रुपये प्रति किलोग्राम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे सुपारी किसानों को अच्छा रेट मिले, इसलिए मोदी सरकार ने सुपारी के इम्पोर्ट पर 100% कस्टम ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार 2017 में MIS के तहत सुपारी की खरीद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणापत्र में इस बात को लाने वाली है कि राज्य में बनने वाली येदुरप्पा सरकार कर्नाटक में सुपारी के औषधीय गुणों पर रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी।

कॉफी किसानों की समस्या पर प्रकाश डालते हुये भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में कॉफी के बगीचे भी सूखते जा रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि कॉफी उत्पादक किसानों की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि कर्नाटक में येदुरप्पा सरकार बनने पर चिकमंगलूर में हर साल इंटरनेशनल कॉफ़ी व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का भला कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वह भ्रष्टाचार की पोषक है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विकास के लिए जो भी पैसा मोदी जी भेजते हैं, वह राज्य के विकास कार्यों में लगने के बजाय सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विकास के लिये राज्य से सिद्धारमैया सरकार का जाना आवश्यक है और यह केवल भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) केवल कुछ वोट काट सकती है। वह कर्नाटक को सिद्धारमैया के कुशासन, भ्रष्टाचार, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से निजात नहीं दिला सकती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रति अटूट आस्था जताते हुए श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विगत पांच वर्षों के शासनकाल में सिद्धारमैया सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है, सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी है।

**सौंदत्ती येल्लम्मा (बेलगावी)**

## भाजपा कर्नाटक को मॉडल स्टेट बनायेगी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 मई को बेलगावी (कर्नाटक) के सौंदत्ती येल्लम्मा में आयोजित विशाल जन-सभा को संबोधित किया और कर्नाटक की जनता से राज्य के विकास के लिए श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेलगावी दक्षिण विधानसभा में कृष्णा होटल, बडागांव से शिवाजी गार्डन तक और बेलगावी उत्तर विधानसभा में किर्लोस्कर रोड, भोगरसे से कावेरी कोल्ड ड्रिंक्स तक भव्य रोड शो किया।

श्री शाह ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पिछले पांच वर्षों में 3500 से अधिक किसान सिद्धारमैया सरकार की गलत नीतियों एवं अनदेखी के कारण आत्महत्या करने को विवश हुये हैं। उन्होंने कहा कि जब सिद्धारमैया से इस बारे में सवाल किया जाता है तो असंवेदनशील जवाब देते हुये कहते हैं कि किसान तो पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया जी, आपकी सरकार आने के बाद कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या दर में लगभग 173% की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से केवल तीन साल में किसानों की आत्महत्या में लगभग 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बनने वाली भाजपा की येदुरप्पा सरकार किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही किसानों के एक लाख रुपये तक का ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है जो किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बेलगावी के कई गन्ना किसानों का चीनी मिलों में बकाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धारमैया सही ढंग से काम करते तो महादायी नदी का पानी कब का बेलगावी और इसके आस पास के क्षेत्र में पहुंच गया होता। उन्होंने कहा कि अहंकार के कारण सिद्धारमैया ने अन्य राज्यों से ठीक से चर्चा नहीं की जिसके कारण इस क्षेत्र को महादायी नदी का पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राज्य की जनता का आह्वान करते हुये कहा कि आप श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार कर्नाटक में बनाइये, 6 महीने में ही महादायी का पानी बेलगावी की धरा को सिंचित और पल्लवित करने लगेगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री शाह ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना और उसे समाज की मुख्यधारा में शामिल करना लेकिन कांग्रेस आजादी के 70 सालों में भी ऐसा करने में विफल रही। श्री शाह ने राज्य की जनता से अपील करते हुये कहा कि यदि कर्नाटक को विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर करना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में राज्य में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में देखते ही देखते कर्नाटक पांच वर्षों के भीतर ही एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो जाएगा। ■

# भाजपा घोषणापत्र जारी

कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने 4 मई को विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प-पत्र जारी करते हुए सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को एक लाख रुपए तक कर्ज माफी देने का वायदा किया। बेंगलूरू में अपनी पार्टी का संकल्प-पत्र (घोषणा-पत्र) जारी करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए एक लाख रुपयों तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। भाजपा के घोषणापत्र में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 5000 करोड़ रुपयों के विशेष 'रैयता बंधु मार्केट इंटरवेशन फंड' बनाने की घोषणा की है। बंजर भूमि के मालिक किसानों को भी 10,000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की गई है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं पर 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का वायदा भी किया गया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में गोपालन को संरक्षण एवं बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। घोषणापत्र में गायों को बचाने के लिए गोहत्या कानून को पुनर्जीवित करने एवं गोपालन को बढ़ावा देने के लिए गोसेवा आयोग बनाने की घोषणा की गई है।

घोषणापत्र में महिलाओं के लिए बीपीएल वर्ग की कन्याओं के विवाह के समय उन्हें तीन ग्राम सोने का मंगलसूत्र एवं 25,000 रुपये की सहायता देने की बात कही गई है। यही नहीं, गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करनेवाली महिलाओं को स्मार्ट फोन भी देने का वादा किया गया है। सिद्धारामैया सरकार में लोकायुक्त के अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया गया था। उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन किया गया था। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लोकायुक्त के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने की बात कही है। ■

## प्रमुख घोषणाएं

- किसानों को पंप सेट के लिए दस घंटे के लिए फ्री बिजली
- गौ-हत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा
- जानवरों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपये
- भाग्यलक्ष्मी स्कीम के तहत 1-2 लाख रुपये मिडिल क्लास और लोअर क्लास की महिलाओं को दिये जाएंगे
- शादी के मौके पर 3 ग्राम का मंगलसूत्र सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दिये जाएंगे
- ओबीसी जाति के लोगों के लिए सुविधा घर, 7500 करोड़ रुपये का बजट
- 400 ST बच्चों को विदेश में स्पॉन्सर पढ़ाई
- 24x7 एंटी करप्शन हेल्पलाइन की सुविधा
- राज्य में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने पर जोर
- बेंगलुरु को गार्बेज-मुक्त किया जाएगा
- राज्य में हाइवों का विकास किया जाएगा

# कश्मीर की वेदी पर वह आत्मबलिदान

| अटल बिहारी वाजपेयी |

भारतीय जनसंघ के प्रधान डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का आत्मबलिदान अन्याय के परिमार्जन के लिए हुआ। अब्दुल्लाशाही के अमानुषिक अत्याचारों से त्रस्त जम्मू की जनता की करुण पुकार सुनकर वे चुप न रह सके। माँ-बहनों के अपमानों की गाथाएँ, उनकी अपार सहनशक्ति के लिए भी असह्य हो गयीं। भारतमाता के पुनः खण्डित हो जाने का खतरा देखकर उनका हृदय विकल हो उठा। शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए राष्ट्र के जीवन तथा सम्मान को पुनः एक बार दाँव पर लगाने की कांग्रेस की नीति का विरोध करना, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अनेक बार लोकसभा में अपने भाषणों में उन्होंने प्रधानमंत्री पं० नेहरू से कश्मीर के प्रश्न को राष्ट्रहित की दृष्टि से सुलझाने की प्रार्थना की। सारे देश में कश्मीर दिवस' का आयोजन कर कश्मीर राज्य को पूरी तरह भारत में मिलाने की माँग की गई। शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों की पृथकतावादी मनोवृत्ति का विरोध किया गया। पर भारत सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

जनमत की खुली अवज्ञा कर नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ ऐसा समझौता कर लिया, जिससे न केवल भारत की एकता पर कुठाराघात हुआ, अपितु जम्मू तथा लद्दाख के 15 लाख निवासियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। समझौते के अंतर्गत कश्मीर को अपना पृथक् विधान, पृथक् प्रधान तथा पृथक् निशान रखने का अधिकार दे दिया गया। सारे देश में उस समझौते का विरोध हुआ। डॉ० मुखर्जी ने लोकसभा में अपने अकाट्य तर्कों तथा प्रबल प्रमाणों से उस समझौते को भारत तथा कश्मीर दोनों के लिए अहितकर सिद्ध किया, किन्तु नेहरू जी अपने दुराग्रह पर डटे रहे। यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर राज्य की वैधानिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन करने से पूर्व उन्होंने जम्मू तथा लद्दाख की जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श करना भी आवश्यक नहीं समझा।

इस स्थिति में, जम्मू की जनता के सम्मुख भारत में पूरी तरह शामिल किये जाने की माँग करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहा। 5 वर्ष तक सभी भेदभाव तथा दमन के बीच वह इस आशा से चुप रही कि जल्दी ही कश्मीर पर भारत का संविधान लागू हो जायेगा और भारतीय नागरिक के नाते उसे भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उपयोग करने तथा अपने विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार मिल जायेगा। लेकिन जुलाई समझौते ने उसकी इस आशा पर पानी फेर दिया। उसकी आँखों के आगे सन् 1947 का भयावह इतिहास नाचने लगा। शेख अब्दुल्ला की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण उसे अपने ही सामने एक नया पाकिस्तान बनते हुए दिखायी दिया। वह कमर बाँधकर प्रजापरिषद् के नेतृत्व में खड़ी हो गई। अपने लिए नहीं, मातृभूमि की अखण्डता के लिए, उसने शांतिमय आंदोलन छेड़ दिया।

उस देशभक्तिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए अब्दुल्ला सरकार ने पंजाब पुलिस की सहायता से जम्मू की जनता पर जो अमानुषिक अत्याचार ढाये, उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं। शहीदों का रक्त अभी गीला है और चिता की राख में चिनगारियाँ बाकी हैं। उजड़े हुए सुहाग और जंजीरों में जकड़ी हुई जवानियाँ उन अत्याचारों की गवाह हैं।

डॉ० मुखर्जी ने 'प्रजापरिषद् तथा सरकार के बीच समझौता कराने की पूरी कोशिश की। इसके लिए नेहरू जी तथा शेख अब्दुल्ला से लम्बा पत्र-व्यवहार भी किया। किन्तु नेहरू जी के दुराग्रह ने उनके प्रयत्नों को पूर्ण विफल कर दिया। "बिना लड़े सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा"—यह गर्व घोषणा करने वाले दुर्योधन की दुखदायी स्मृति को सजीव करते हुए उन्होंने 'प्रजापरिषद्' से बात तक करने से इनकार कर दिया।

अब डॉ० मुखर्जी के सम्मुख संघर्ष का शंख फूंकने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न रहा। समझौता न होने की दशा में जम्मू की जनता के समर्थन में शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देने के लिए वे वचनबद्ध थे। भारतीय जनसंघ के कानपुर अधिवेशन (1952) में स्वीकृत प्रस्ताव को अमल में लाने का अवसर आ चुका था। 5 मार्च को उन्होंने दिल्ली में अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना के लिए, तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की विजय के लिए और विघटन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता के लिए, महात्मा गांधी का नाम लेकर संघर्ष की घोषणा कर दी। समस्त देशवासियों को 'बलिदान के पथ पर पाँव बढ़ाने के लिए ललकारते हुए उन्होंने कहा-"हम सत्य के लिए संघर्ष छेड़ रहे हैं। न्याय की रक्षा के लिए बलि-पथ पर पाँव बढ़ा रहे हैं। अत्याचारों की अग्निपरीक्षा हमारे रूप को और भी निखार देगी। दमन का दमन हमारे माथे पर विजय का तिलक बनकर चमकेगा। बलिदानों के गौरवपूर्ण इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय और जुड़ जायेगा। आओ, उस इतिहास के निर्माण में हाथ बटाने के लिए कमर कस मैदान में कूद पड़े। सच्चे स्वराज्य तथा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना का एकमेव यही मार्ग है। उसकी विजय निश्चित है।"

6 मार्च को जम्मू के शहीदों की अस्थियों के जुलूस पर लगे प्रतिबंध को तोड़कर, उन्होंने संघर्ष का श्रीगणेश कर दिया। स्वयं कारागार की ओर अग्रसर होकर अनुयायियों का मार्गदर्शन किया। उनकी गिरफ्तारी से सारे देश में तहलका मच गया। सबका ध्यान प्रजापरिषद् के आंदोलन की ओर खिंच गया। देश में एक नई चेतना जाग उठी।

सरकार की दमन-नीति के नीचे पिसती-कराहती जनता को आशा का एक सन्देश मिला। दिल्ली और पठानकोट में प्रजापरिषद् की माँगों के समर्थन में लाक्षणिक सत्याग्रह छिड़ गया। हजारों व्यक्ति घर-बार की चिंता छोड़कर राष्ट्रीय एकता के इस महान् अनुष्ठान में अपना

योग देने के लिए डॉक्टर साहब के चरण-चिह्नों का अनुसरण कर खुशी-खुशी जेल जाने लगे।

सरकार ने डॉक्टर साहब को गिरफ्तार तो कर लिया, किन्तु वह अधिक दिन उन्हें जेल में न रख सकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के मुँह पर एक करारी चपत लगवाकर डॉक्टर साहब अपने अन्य साथियों सहित जेल से बाहर आ गये। तानाशाही के गढ़ पर उनका यह प्रथम सफल प्रहार था, जिसने कांग्रेस सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के रूप में संसार के सम्मुख बेपर्दा खड़ा कर दिया।

जेल से बाहर आकर डॉक्टर साहब ने आंदोलन को उग्र बनाने के साथ-साथ सरकार के साथ समझौता करने का यत्न भी जारी रखा। लोकसभा में वित्त विनियोग विधेयक पर भाषण करते हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री से पुनः एक बार जम्मू की जनता की पुकार पर कान देने की प्रार्थना की। दिल्ली में सत्याग्रहियों के प्रति पुलिस द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार की ओर भी उन्होंने सरकार का ध्यान खींचा। पर नेहरू जी ने उनकी सभी अपीलों को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉ० मुखर्जी की नीयत पर आक्षेप किया और तर्क का उत्तर तर्क से देने के बजाय अपशब्दों पर उतर आये। यद्यपि दिल्ली में उस समय हुए उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार तथा जनसंघ और हिन्दूसभा की शानदार जीत ने एक बार फिर यह बता दिया था कि जम्मू-आंदोलन को जनता का समर्थन प्राप्त है। किन्तु, फिर भी नेहरू जी जनमत को अनसुना कर अपने हठ पर अड़े रहे। इस स्थिति में डॉक्टर साहब ने आंदोलन को अधिकाधिक तीव्र करने में ही समस्या के समुचित समाधान की संभावना देखी। अतः उन्होंने देश के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा कर, जम्मू-आंदोलन के वास्तविक उद्देश्यों को जनता के सामने रखा। सर्वत्र कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष बातचीत करके उन्होंने आंदोलन के प्रति जनता के रुख का पता लगाया। इन दौरों से उनकी यह धारणा दृढ़ हो गई कि सारा देश कश्मीर को अविलम्ब भारत के अविभाज्य अंग के रूप में देखने के लिए उत्सुक है और वह जम्मू-आंदोलन की सफलता चाहता है।

आंदोलन को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, यह विश्वास कर लेने के बाद डॉक्टर साहब ने नेहरू जी के इस कथन को कसौटी पर कसने का निश्चय किया कि जम्मू-कश्मीर सौ फीसदी भारत का अंग है। इसके लिए उन्होंने बिना परमिट जम्मू जाने का संकल्प किया। 8 मई को दिल्ली से पंजाब के दो दिन के दौरे पर रवाना होते समय उन्होंने वक्तव्य में कहा कि जम्मू जाने में उनका उद्देश्य किसी प्रकार की अशांति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि गतिरोध को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक रीति से हल करने के लिए एक और प्रयत्न करना है। परमिट न लेने के निश्चय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक के नाते देश के किसी भी भाग में जाने का उन्हें पूर्ण अधिकार है और चूँकि नेहरू जी आये दिन कहते रहते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत में सौ फीसदी शामिल हो चुके हैं, अतः उन्होंने बिना परमिट के वहाँ जाने का फैसला किया है।

डॉक्टर साहब के इस कदम की सारे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली से पठानकोट तक हर स्टेशन पर हजारों नर-नारियों ने, 'परमिट सिस्टम तोड़ दो' के गगनभेदी नारों से उनका स्वागत किया और कहाँ मिलेंगे-जम्मू में' का घोष कर उनको अपने समर्थन का विश्वास दिलाया। अनुमान था कि डॉक्टर साहब को पठानकोट पहुँचने से पहले ही कहीं गिरफ्तार कर लिया जायेगा; लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डर से सरकार ने न केवल उन्हें पठानकोट तक जाने दिया, बल्कि बिना परमिट जम्मू में प्रविष्ट होने पर भी अपनी ओर से कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया।

गुरुदासपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर श्री वशिष्ठ ने पठानकोट में डॉक्टर साहब को बताया कि वे अपनी पार्टी के साथ बिना परमिट जम्मू जा सकते हैं। भारत सरकार उनके मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू में बख्शी गुलाम मोहम्मद डॉक्टर साहब से भेंट करेंगे। लेकिन जब वे अपने साथियों सहित भारत की सीमा को पार कर जम्मू की सीमा में स्थित रावी के पुल पर पहुँचे, तो कश्मीर मिलिशिया उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वहाँ कठुआ के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट ने उन्हें राज्य की सीमा में न घुसने का आदेश दिया। डॉक्टर साहब ने इसे मानने से इन्कार कर दिया, जिस पर उन्हें कश्मीर सुरक्षा विधान के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी से पूर्व उन्होंने भारतीय जनता के नाम अपने संदेश में कहा-"मैं जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हैं, लेकिन एक कैदी की हैसियत से।" उनका यह संदेश बिजली की भाँति सारे देश में फैल गया। कोने-कोने से सत्याग्रहियों के जत्थे अपने नेता के मार्ग पर निर्भय होकर पाँव बढ़ाते हुए बिना परमिट जम्मू में प्रविष्ट होने लगे। डॉक्टर साहब के एक ही हल्के पदाघात से सरकार द्वारा कश्मीर और भारत के बीच खड़ी की गई परमिट की कृत्रिम दीवार ढहकर चूर-चूर हो गई। साथ ही नेहरू जी के इस असत्य का भी पर्दाफाश हो गया कि कश्मीर सौ फीसदी भारत का अंग है।

## 23 जून '53 की वह रात

गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर साहब को श्रीनगर ले जाया गया, जहाँ नजरबंदी की अवस्था में गिरफ्तारी के 43वें दिन 23 जून की रात को बड़े रहस्यमय ढंग से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

किन्तु वे मरे नहीं, विभाजित भारत की अवशिष्ट एकता को बनाये रखने के लिए राष्ट्र की वेदी पर अपने सर्वस्व की बलि चढ़ाकर अमर हो गये। औरों को बलिदान के पथ पर आने का आह्वान करते-करते स्वयं बलि हो गये। ध्येय की सिद्धि के लिए अपने अनमोल जीवन को निछावर कर गये। विघटनकारी मनोवृत्तियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भारतमाता के मस्तक को कश्मीर के किरीट से मण्डित रखने के लिए अपने प्राणों पर खेले गये। लोकतंत्र की रक्षा के लिए नीव के पत्थर बन गये। तानाशाही के शिकार हो गये। अन्धकार की शक्तियों से संघर्ष करते-करते अनन्त ज्योति में विलीन हो गये। अपने धर्म का पालन करते हुए कर्मभूमि में सो गये। ■

(डॉ. चंद्रिकाप्रसाद शर्मा द्वारा सम्पादित पुस्तक **'अटल बिहारी वाजपेयी : *कुछ लेख कुछ भाषण*'** से)

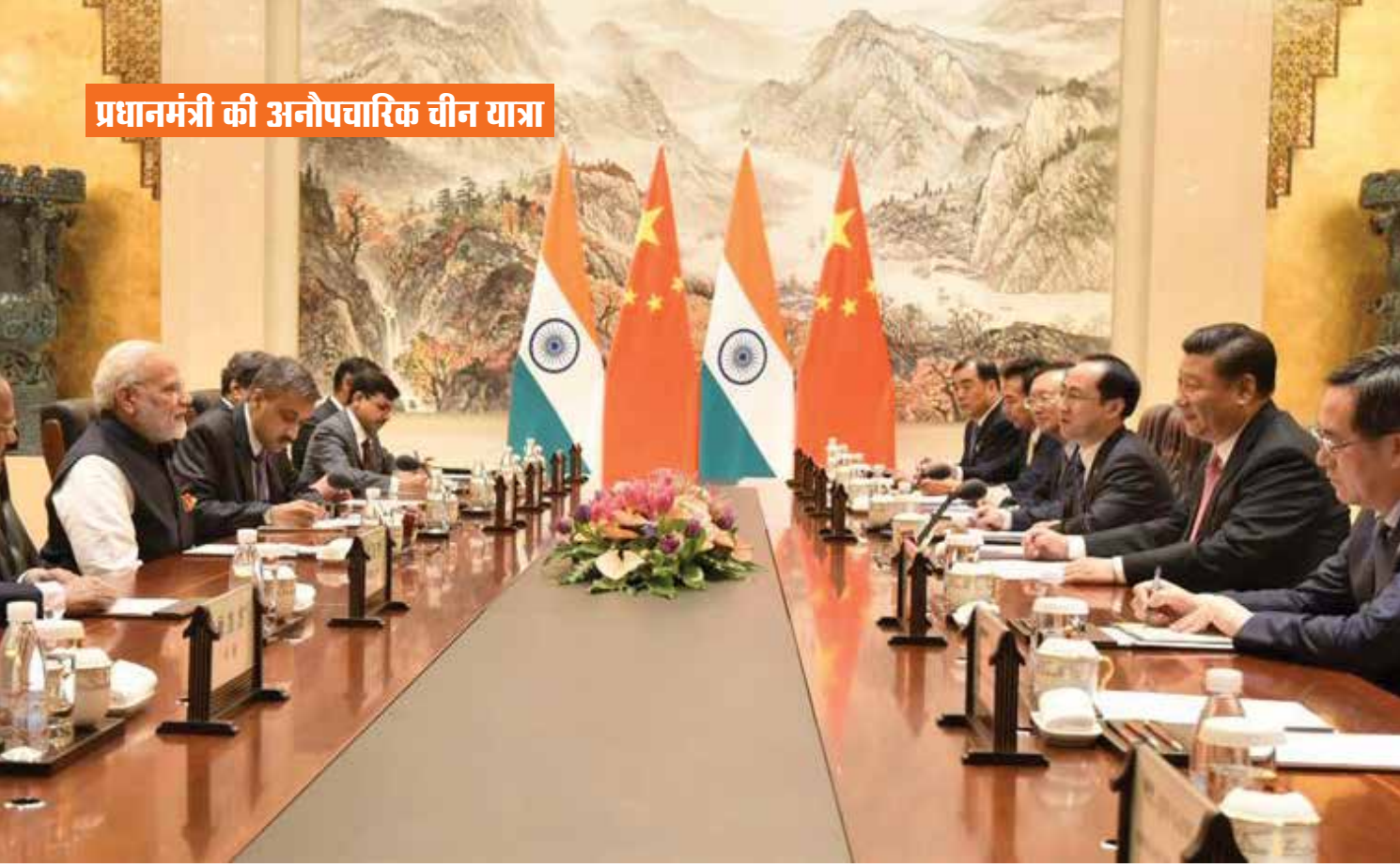

# भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन संपन्न

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन जन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान एवं वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय विकास के लिये उनकी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण पर विस्तार से बातचीत करने के लिये 27-28 अप्रैल 2018 को वुहान में उनके बीच प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

उनका मानना है कि भारत और चीन का दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं एवं महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में रणनीतिक और निर्णय लेने की स्वतंत्रता सहित क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है। उनका मानना था कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित रिश्ते मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक सकारात्मक कारक साबित होंगे। वो इस बात पर भी सहमत हुये कि द्विपक्षीय संबंधों का समुचित प्रबंधन क्षेत्रीय विकास एवं स्थिरता के लिये सहयोगकारी रहेगा और एशिया की सदी के निर्माण के लिये अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेगा। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय आधुनिकीकरण और अपने लोगों को अधिक समृद्ध बनाने के लिये एक करीबी विकासात्मक साझेदारी को परस्पर लाभकारी और स्थायी तरीके से सशक्त बनाने का निश्चय किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री शी ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भारत-चीन संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। भावी संबंधों के लिये संभव सबसे वृहद मंच के निर्माण के लिये वे पहले से स्थापित प्रणालियों के जरिये मौजूदा सम्मिलन को और विकसित करने के लिये अपने प्रयासों को व्यापक रूप से बढ़ाने पर भी सहमत हुये। वे इस बात पर भी सहमत हुये कि एक दूसरे की संवेदनशीलताओं, चिंताओं और आकांक्षाओं के महत्व को दिमाग में रखते हुये दोनों देशों के मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग और समग्र संबंधों के संदर्भ में सुलझाने के लिये दोनों पक्षों में पर्याप्त परिपक्वता और बुद्धिमत्ता है।

दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा से संबंधित विषय पर काम कर रहे विशेष प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे काम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और उनसे एक न्यायोचित, समुचित और परस्पर रूप से स्वीकार्य समझौते को हासिल करने के लिये उनकी कोशिशें तेज करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक हित में भारत-चीन सीमा क्षेत्र के सभी हिस्सों में शांति और शांतिचित्तता बनाये रखने के महत्व पर बल दिया। इसकी प्राप्ति के लिये उन्होंने अपनी सेनाओं को विश्वास एवं आपसी समझ विकसित करने और सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन में पूर्वानुमान लगाने और उन्हें प्रभावकारी बनाने के लिये रणनीतिक मार्गनिर्देशन दिये। इसके लिये दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं को, दोनों पक्षों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ाने के

जिन उपायों पर सहमति बनी है, उन्हें ईमानदारी से लागू करने के निर्देश दिये जिसमें परस्पर एवं समान सुरक्षा भी शामिल है और सीमा क्षेत्रों में घटनाओं को रोकने के लिये मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं और जानकारी के आदान-प्रदान की प्रणालियों को सशक्त बनाना भी शामिल है। दोनों नेता दोनों देशों के बीच मौजूद लाभकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुये द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को एक संतुलित और स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुये। उन्होंने लोगों के बीच आपसी संपर्क और घनिष्ठ सांस्कृतिक संपर्कों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर भी चर्चा की और इस दिशा में एक नयी व्यवस्था की स्थापना की संभावना को तलाशने पर भी सहमत हुये।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री शी ने इस बात पर बल दिया कि दो महत्वपूर्ण देशों के तौर पर भारत और चीन के व्यापक और परस्पर जुड़े हुये क्षेत्रीय और वैश्विक हित हैं। दोनों नेता साझा हित के सभी विषयों पर अधिक चर्चा के जरिये रणनीतिक संवाद को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुये। उनका मानना है कि ऐसा रणनीतिक संवाद आपसी समझ पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान देगा।

दोनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और चीन दोनों ने अपने-अपने विकास और आर्थिक प्रगति के जरिए विश्व शांति और समृद्धि में अलग-अलग ढंग से व्यापक योगदान दिया है और दोनों ही देश भविष्य में वैश्विक विकास के लिये एक इंजिन की तरह काम करते रहेंगे। दोनों नेताओं ने एक खुले, बहुध्रुवीय, बहुलवादी एवं भागीदारी पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के महत्व को दोहराया, जो सभी देशों को उनके विकास के लक्ष्यों को हासिल करने योग्य बनायेगी और विश्व के सभी क्षेत्रों से निर्धनता और असमानता के उन्मूलन में सहयोग करेगी। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करने के उनके अपने प्रयासों पर भी बातचीत की।

दोनों नेताओं ने वैश्विक समृद्धि और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये विदेशी नीति पर अपने-अपने दृष्टिकोण के बारे में एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किये। दोनों नेता वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, स्थायी विकास और खाद्य सुरक्षा और अन्य चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिये एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से संयुक्त रूप से योगदान देने पर भी सहमत हुये। उन्होंने बहुपक्षीय वित्तीय एवं राजनीतिक संस्थाओं के सुधार के महत्व पर बल दिया, ताकि इन संस्थाओं को और अधिक प्रतिनिधित्वकारी और विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति और संवेदनशील बनाया जा सके।

दोनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि दोनों देशों के व्यापक विकास संबंधी अनुभव और राष्ट्रीय क्षमताओं को देखते हुये दो महत्वपूर्ण देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर भारत और चीन को 21वीं सदी में मानव जाति द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिये अनोखे और स्थायी समाधान प्रदान करने में बढ़त लेने के लिये आपस में हाथ मिला लेने चाहिये। इनमें शामिल हैं रोगों का मुकाबला करना, आपदाओं के खतरे को कम करने के कार्यों में समन्वय, जलवायु परिवर्तन से निपटना और डिजिटल सशक्तीकरण। वे मानव जाति के व्यापक हित में इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने और ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिये एक वैश्विक संगठन बनाने पर भी सहमत हुये।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री शी ने आतंकवाद के सम्मिलित खतरे को पहचाना और आतंकवाद के सभी प्रकारों और

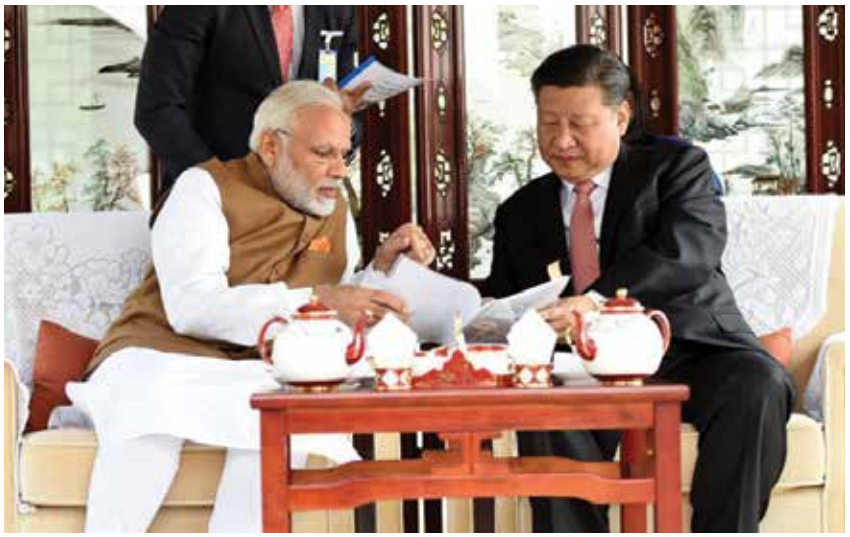

सभी रूपों के प्रति अपने प्रबल प्रतिरोध और जोरदार भर्त्सना को फिर से दोहराया। उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग करने के लिये अपने आप को समर्पित किया।

दोनों नेताओं ने एक प्रत्यक्ष, स्वतंत्र और विचारों के खुले आदान-प्रदान के लिये इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसर की प्रशंसा की और ऐसी अन्य बातचीत आयोजित करने की उपयोगिता पर सहमत हुये। इस भविष्योन्मुख संवाद ने उनके ऐसे दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और परिकल्पना के संबंध में उनके रणनीतिक संवाद के स्तर को ऊपर उठाया है, जो उनके घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक नीतिगत विकल्पों को दिशा देते हैं। इसने उन्हें भारत-चीन संबंधों की भावी दिशा के लिये एक साझा समझ विकसित करने में भी मदद की, जो एक दूसरे की विकास संबंधी आकांक्षाओं और परस्पर संवेदनशीलता के साथ मतभेदों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के प्रति परस्पर सम्मान पर आधारित है। ■

# बाबा साहेब ने हाशिये पर खड़े करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अप्रैल को 'मन की बात' कार्यक्रम की 43वीं कड़ी में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष दिवस है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने विश्वभर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। यह बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करने का, संकल्प करने का और चलने का हम सबके दायित्व को पुनःस्मरण कराता है।

श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध समानता, शांति, सदभाव और भाईचारे की प्रेरणा शक्ति है। यह वैसे मानवीय मूल्य हैं, जिनकी आवश्यकता आज के विश्व में सर्वाधिक है। बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर जोर देकर कहते हैं कि उनकी सोशल फिलॉसोफी में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रेरणा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो हाशिये पर खड़े करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया। करुणा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लोगों की पीड़ा के लिए यह करुणा भगवान बुद्ध के सबसे महान गुणों में से एक थी। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों की यात्रा करते रहते थे। वह अपने साथ भगवान बुद्ध के समृद्ध विचारों को ले करके जाते थे और यह सभी काल में होता रहा है। समूचे एशिया में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें विरासत में मिली हैं। वह हमें अनेक एशियाई देशों; जैसे चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, म्यांमार कई अनेक देश वहां बुद्ध की इस परंपरा, बुद्ध की शिक्षा जड़ों में जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि हम बौद्ध पर्यटन के लिए इन्फ्रॉस्ट्रक्टर विकसित कर रहे हैं, जो दक्षिण-पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण स्थानों को, भारत के खास बौद्ध स्थलों के साथ जोड़ता है।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की भी अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत सरकार कई बौद्ध मंदिरों के पुनरुद्धार कार्यों में भागीदार है। इसमें म्यांमार में बागान में सदियों पुराना वैभवशाली आनंद मंदिर भी सम्मलित है। आज विश्व में हर जगह टकराव और मानवीय पीड़ा देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा घृणा को दया से मिटाने की राह दिखाती है। मैं दुनिया भर में फैले हुए भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले, करुणा के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले - सबको बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमयी कामना करता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध से पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, ताकि हम उनकी शिक्षा पर आधारित एक शांतिपूर्ण और करुणा से भरे विश्व का निर्माण करने में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकें। आज जब हम भगवान बुद्ध को याद कर रहे

हैं। आपने लॉफिंग बुद्धा की मूर्तियों के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि लॉफिंग बुद्धा गुड लक लाते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्माईलिंग बुद्धा भारत के रक्षा इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ी हुई है। अब आप सोचते रहे होंगे कि स्माईलिंग बुद्धा और भारत की सैन्य-शक्ति के बीच क्या संबंध है?

श्री मोदी ने कहा कि आपको याद होगा आज से 20 वर्ष पहले 11 मई, 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था और उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्वभर में फैले हुए भारतीय समुदाय में नया आत्मविश्वास उजाग़र हुआ था। वह दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। 11 मई, 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताक़त का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य-शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है- अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सब के साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। मई, 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ़ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वह महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक

शेष पृष्ठ संख्या 33 पर...

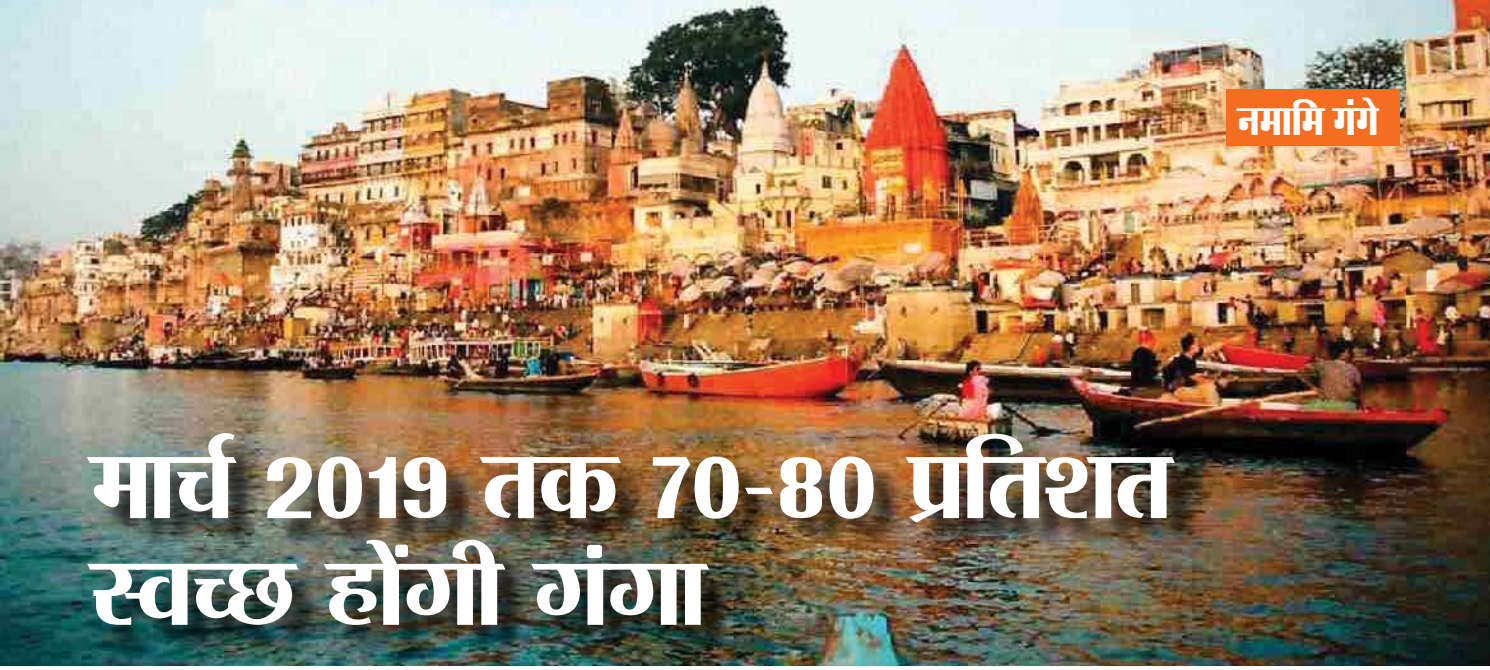

# मार्च 2019 तक 70-80 प्रतिशत स्वच्छ होंगी गंगा

"हम मार्च 2019 तक गंगा को 70 से 80 प्रतिशत स्वच्छ बनाने की उम्मीद करते हैं। यह एक सामान्य धारणा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। 251 प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) को बंद किया गया है और जीपीआई के नियमों की अवहेलना करने के लिए उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।" उक्त बातें केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 10 मई को नई दिल्ली में कही। मंत्री महोदय ने कहा कि 938 उपक्रमों में वास्तविक समय पर प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। 211 ऐसे नालों की पहचान की गई है जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। नाले के पानी के परिशोधन के लिए 20 एसटीपी निर्मित किए गए हैं।

केन्द्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि गंगा तट पर स्थित लगभग 4470 गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गए है। हम लोग अब ओडीएफ प्लस की रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। ठोस-द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, गांवों व शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाना तथा जन जागरूकता अभियान चलाना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुश्री भारती ने कहा कि हमारा मंत्रालय गंगा ज्ञान परियोजना पर काम कर रहा है, जो गंगा तट पर बसे गांव के सम्पूर्ण विकास पर आधारित है। गंगा ग्राम में जैविक खेती, संरक्षण परियोजना, ठोस व द्रव अपशिष्ट का उचित निपटान तथा तालाबों के पुनर्रुद्धार पर विशेष जोर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि नमामि गंगे एक वृहद कार्यक्रम है, जिसमें गंगा सरंक्षण से संबंधित सभी पुरानी व वर्तमान की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा और यह दिसम्बर 2020 को समाप्त होगा।

'नमामि गंगे कार्यक्रम' के तहत सीवर अवसंरचना, घाटों व श्मशान स्थलों का विकास, नटी तट विकास, नदी सतह की साफ-सफाई, जैव विविधता सरंक्षण, वानिकीकरण, ग्रामीण स्वच्छता जैसी गतिविधियों पर आधारित कुल 195 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

195 में से 102 परियोजनाओं के तहत 2369 एमएलडी क्षमता के नये सीवर शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, 887 एमएलडी क्षमता वाले संयंत्रों की मरम्मत की जायेगी तथा गंगा व यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए 4722 किलोमीटर लम्बा सीवर नेटवर्क बनाया जायेगा। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 एसटीपी परियोजनाएं (वाराणसी और हरिद्वार) हाईब्रिड एनयुटी पीपीपी मोड (एचएएम) के तहत चलाई जा रही है। एचएएम के तहत मंजूर की गई परियोजनाएं हैं- उत्तर प्रदेश में नैनी, झुसी, फाफमाऊ, उन्नाव, शुक्लगंज, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और फर्रुखाबाद; बिहार में दीघा, कंकड़बाग और भागलपुर; पश्चिम बंगाल में हावड़ा, बाली और टॉली नाला (कोलकाता), कमरहटी और बड़ानगर।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 'एक नगर एक संचालक' को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत सात शहरों (कानपुर, इलाहाबाद, पटना, हावड़ा, भागलपुर, मथुरा और कोलकाता) के एसटीपी परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है और एचएएम के तहत निविदा जारी की गई है। चार (कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा और कोलकाता) के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उन दस शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनके द्वारा कुल सीवर का 64 प्रतिशत प्रवाहित होता है।

नदी तट विकास के तहत 152 घाटों तथा 54 श्मशान घाटों का विकास किया जा रहा है और इसके 2018 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित लागत 683.32 करोड़ रुपये है। 254.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना नदी तट विकास परियोजना पूरी होने के अंतिम चरण में है। इसके तहत 20 घाटों तथा 6.6 किलोमीटर लम्बा टहलने का मार्ग विकसित किया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 44 जल गुणवत्ता निगरानी प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा रहा है। ■

# बदलती दुनिया में उभरता भारत

| गुरजीत सिंह |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया यूरोपीय दौरा कई मायनों में खास रहा। इस बार परिवेश और मेलजोल की प्रक्रिया का ढांचा अलग था। राष्ट्रमंडल सम्मेलन से इतर नॉर्डिक देशों के साथ संवाद और बर्लिन में कुछ समय रुकना नई रणनीति का ही हिस्सा था। मोदी सरकार में विदेश नीति में मेलजोल को लेकर प्राथमिकताएं शुरुआत से ही तय थीं। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस के सभी राष्ट्रप्रमुखों को आमंत्रित किया। इसके बाद अमेरिका, चीन, रूस, जापान और जर्मनी के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देशों को साधने की कवायद शुरू हुई। फिर इसका दायरा और बढ़ा और कई क्षेत्रीय संगठन साथ आए। इस कड़ी में 2015 में अफ्रीका सम्मेलन और इस साल आसियान का नाम लिया जा सकता है।

अब चीन में चल रहा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ मध्य एशिया को आपसी जुड़ाव के लिए एक नया मंत्र देगा। नॉर्डिक पहल भी इस खांचे में पूरी तरह सटीक बैठती है। बहुपक्षीय मेलजोल अब लगातार तेजी पकड़ रहा है। इसी महीने संपन्न अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और राष्ट्रमंडल बैठक में भी यह पूरी तरह झलकता है। प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की शुरुआत स्वीडन के साथ हुई। तमाम देश भारतीय बाजार के आकार और उसके महत्व की अनदेखी नहीं कर सकते और स्वीडन दौरे से यह बात एक बार फिर साबित हुई। स्वीडन मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का प्रबल समर्थक है। भारत में स्वीडन का निवेश लगातार बढ़ने पर है, लेकिन व्यापार सीमित है। साथ ही वह भारतीय छात्रों को भी बड़ी तादाद में आकर्षित कर रहा है।

स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफेन भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आए और उन्होंने भी नॉर्डिक सम्मेलन की सह-मेजबानी में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे के राष्ट्र प्रमुखों ने भी शिरकत की। सम्मेलन का शीर्षक ही था 'भारत-नॉर्डिक सम्मेलनः साझा मूल्य एवं परस्पर समृद्धि।' यह भारत आसियान सम्मेलन की ही तरह था, जिसके लिए वही प्रारूप अपनाया गया। हालांकि नॉर्डिक देशों के लिए यह बहुत अनोखा था, क्योंकि वे समूह के रूप में किसी देश के राष्ट्रप्रमुख की आगवानी नहीं करते। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा से जरूर एक साथ मुलाकात की थी, लेकिन आसियान या ईयू की तरह नॉर्डिक देशों का कोई संगठन नहीं जो उन्हें एक मंच प्रदान करे।

मौजूदा नॉर्डिक परिषद एक संसदीय समूह है और उसके मंत्रियों की परिषद भी उसके बाल्टिक और जर्मनी में शेल्सविग होल्स्टेन के पड़ोसियों से ही संबंध बेहतर बनाने में सक्रिय रहती है। बहरहाल नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में नवाचार और डिजिटल रूपांतरण ही वृद्धि को धार देते हैं और भारत एवं नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते मेलजोल के मूल में यह पहलू शामिल है। इससे दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का अहसास हुआ। यहां यूरोपीय संघ की छाया का भी असर देखने को नहीं मिला। केवल दो नॉर्डिक देश ही यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तीन नाटो सदस्य हैं। इसीलिए व्यापार एवं भूमंडलीकरण में रिश्तों को परवान चढ़ाने पर सहमति बनी जो यूरोपीय संघ के मंच पर दशकों से अटकी हुई है।

भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों को पूरा करने पर भी बात आगे बढ़ी और अगर यह पहल सिरे चढ़ती है, तो मेक इन इंडिया को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। खासतौर से स्वीडन ग्रिपेन लड़ाकू विमान में भारत को सहयोग देने का बहुत उत्सुक है। लंदन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा पड़ाव रहा जहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया। हाल के दौर में ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्ते उस रफ्तार से परवान नहीं चढ़े हैं जैसी गर्मजोशी फ्रांस और जर्मनी के साथ बढ़ी है। विरासत अब वास्तविकता के लिए राह खोल रही है

और ब्रेक्जिट के बाद बने हालात में ब्रिटेन ने भारत को प्राथमिक सूची में रखा हुआ है।

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद भारत के हाथ बेहतर दांव लग सकता है, लेकिन फिर भी आवाजाही और वीजा के मसले अब ब्रिटेन के स्तर पर ही तय होंगे। अब यह ब्रिटेन पर निर्भर करता है कि भारत का भरोसा जीतने के लिए वह इन मुद्दों पर कितनी तत्परता से कदम उठाकर ब्रेक्जिट के बाद अपनी संभावनाएं तलाशता है। भारत चाहता है कि पर्यटकों और छात्रों को आसानी से ब्रिटिश वीजा मिले। वहीं ब्रिटेन को लगता है कि तकनीशियनों के लिए स्पेशल विंडो से इसे सुलझाया जा सकता है। भगोड़ों और अवैध प्रवासियों से जुड़ा राजनीतिक मसला भारत के लिए कड़वाहट का सबब बन गया है। यह बात फ्रांस या जर्मनी के साथ रिश्तों के आड़े नहीं आती।

सामरिक अर्थों में ब्रिटेन अहम साझेदार है जो कई मामलों में भारत जैसी सोच ही रखता है और वैश्विक स्तर पर भारत की व्यापक भूमिका का भी पक्षधर है। हालांकि जर्मनी और फ्रांस के उलट वह भारत को खास पेशकश नहीं कर रहा। उसे चाहिए कि वह बेहतर आव्रजन, व्यापार और मेलजोल के मोर्चे पर कुछ कदम उठाकर इसकी भरपाई करे। लंदन दौरे का दूसरा भाग राष्ट्रमंडल सम्मेलन में बहुपक्षीय सहयोग में नूतन प्रयोग से जुड़ा था। अपनी भूमिका की समझ को लेकर राष्ट्रमंडल की सोच में आया बदलाव इसका खास पहलू रहा। इसके लिए ब्रिटेन के साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के व्यावहारिक आकलन को भी श्रेय देना होगा, जो अन्य सदस्य देशों के साथ मेलजोल में अक्सर मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। साथ ही एक ताकत के रूप में भारत को मान्यता मिलना भी सम्मेलन की एक थाती रही जहां अफ्रीका, कैरेबियन और दक्षिण प्रशांत के तमाम राष्ट्रमंडल देशों ने भारत के साथ सहयोग की जो पींगें बढ़ाईं उन्हें अब बेहतर रूप से मान्यता मिली है।

ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। राष्ट्रमंडल समूह भारत को बेहतर नजरिये से देखता है। जहां ब्रिटिश शक्ति का पराभव हो रहा है वहीं भारत के उदय को देखते हुए उसकी सक्रिय भागीदारी राष्ट्रमंडल को और ताकत देगी। यह राष्ट्रमंडल को फ्रैंकोफिन मॉडल के बजाय लूजोफोन मॉडल की ओर अग्रसर करेगा जहां पुर्तगाल की भूमिका सिकुड़ रही है तो ब्राजील का दबदबा बढ़ रहा है। दौरे का अंतिम पड़ाव बर्लिन रहा। एक साल से भी कम समय में यह मोदी और चांसलर मर्केल की तीसरी बैठक थी। यहां भूमंडलीकरण की रफ्तार तेज करने के उपायों के साथ ही अक्षय ऊर्जा और कौशल विकास में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

भारत की विकास गाथा में और अधिक जर्मन निवेश की जरूरत पर भी बात हुई। यूरोपीय दौरे का लेखाजोखा यही रहा कि इसमें भारतीय रणनीति की नई शैली के दर्शन हुए जो कहीं अधिक व्यावहारिक है। भारत ने दर्शाया कि वह अपनी सहयोगी भूमिका निभाने और मुक्त व्यापार, जलवायु परिवर्तन और नवाचार जैसे वैश्विक लक्ष्यों में अपने योगदान से नहीं हिचकेगा। ■

*लेखक जर्मनी, इंडोनेशिया और इथियोपिया में भारत के राजदूत रहे हैं।*
*(दैनिक जागरण से साभार)*

---

*पृष्ठ संख्या 30 का शेष...*

मज़बूत नेतृत्व के साथ भारत नि.त नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था- "जय जवान जय किसान, जय विज्ञान" आज जब हम 11 मई, 1998 उसका 20वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो 'जय-विज्ञान' का हमें मंत्र दिया है, उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करे। अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएं। देखते-ही-देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद, नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे।

श्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिनों में रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्वभर में रमज़ान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोज़े का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो ख़ुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके सन्देश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार एक इंसान ने पैगम्बर साहब से पूछा- "इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है?" पैगम्बर साहब ने कहा – "किसी गरीब और ज़रूरतमंद को खिलाना और सभी से सदभाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो।" पैगम्बर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वह कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है।

उन्होंने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज़ आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें, इसीलिए रमज़ान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। पैगम्बर मोहम्मद साहब का मानना था कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है न कि धन-दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमज़ान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है यह अवसर लोगों को शांति और सदभावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा। ■

## कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

## प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

# आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

# सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

| सदस्यता | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एक वर्ष | ₹350/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी) | ₹3000/- | ☐ |
| | तीन वर्ष | ₹1000/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी) | ₹5000/- | ☐ |

**(भुगतान विवरण)**

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

**अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें**

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

**कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका**

वुहान (चीन) में भारत–चीन द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन जन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वुहान (चीन) पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत

वुहान ईस्ट लेक पर राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के साथ चाय पर चर्चा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हुबेई प्रांत (चीन) के म्यूजियम को देखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग

**प्रेषण तिथि:** (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
**डाकघर:** लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20